CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Naxalite Activities in the Country

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं अपने देश में फैली नक्सलवादी हिंसा की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): Mr. Chairman, Sir, left wing extremism is a major area of concern with regard to the internal security scenario of the country. Although the effective strength of the movement has remained confined to a few pockets in thecountry in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa, yet the fact remains that its ideology has a negative impact on the country's socio-political life. The problem, therefore, cannot be regarded as a localized phenomenon but is a matter of national concern.

The main extremist groups which have a fairly large organisational structure and resources are the CPML (PWG -- People's War Group) and the MCC (Maoist Communist Centre). These groups are currently engaged in extending their sphere of influence beyond their existing strongholds.

Left wing extremist violence in the country during 1998, when compared with the scenario in the past two years, maintained a downward trend in terms of number of incidents reported as well as in the intensity of violence. Andhra Pradesh and Bihar continued to remain at the forefront of left extremist violence. In the current year, violent incidents have shown a declining trend in all the affected States, except in Bihar, although recent incidents in Madhya Pradesh, Bihar and Andhra Pradesh reflect continuing efforts on the part of left wing extremists to make their presence felt. PWG has mostly targetted the police and other para-military forces deployed on anti-extremist operations as well as suspected informers and local representatives of the people. Their attempt is to inflict as much damage as possible to Government property and property of targetted people.

Keeping in view that left wing extremism was assuming serious dimensions in the affected States. A meeting of the Chief Ministers of the concerned States was convened at Hyderabad on 15.6.1998 to review the action being taken by the States in curbing left wing extremism as well as to prepare a strategy for tackling the problem effectively.As a follow-up of the decisions taken at this meeting, the Ministry .of Home Affairs set up a

Co-ordination Centre, headed by the Unioin Home Secretary with Chief Secretaries and Directors General of Police of the States affected by left wing extremism as its members. Among the important decisions taken are that the States should prepare Action Plans incorporating the security as well as the development aspects in respect of the affected areas. The Action Plans have so far been received from the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa only and have accordingly been recommended to the Planning Commission. These are being considered by the Planning Commission in consultation with the concerned States.

The Government has also formulated a scheme for reimbursement to the extent of 50 per cent of the security related expenditure incurred by States in tackling the problem of left wing extremism, covering the period from 1.4.1996 to 31.3.2001. So far, under this scheme, amounts of Rs. 10 crores, Rs. 5 crores, Rs. 3.58 crores and Rs. 1.96 crores approximately, have been released to the Governments of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa and Maharashtra, respectively.

In addition, the Central Government has taken various other measures to help the States to fight the menace such as holding of co-ordination meetings with the States concerned, sharing of intelligence, training of police personnel in anti-extremist operations, upgrading of weapons and making available Central para-military forces as and when required by the States.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa) : Sir, I would like to have your guidance.

MR. CHAIRMAN : Now, nothing can be raised.

SHRI EDUARDO FALEIRO : All right, I am walking out in protest against the manner in which I was stopped to raise an issue.

(At this stage, the hon. Member left the Chamber)

MR. CHAIRMAN : It is a misdemeanour on the part of the hon. Member to walk-out like that.

श्री संजय निरूपम : चेयरमैन साहब, माननीय गृह मंत्री महोदय ने देश में फैली नक्सली हिंसा विशेषकर पांच राज्यों बिहार मध्य प्रदेश, महाष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उडीसा में है और इससे उत्पन्न समस्या के ऊपर अपना बयान सदन के सामने रखा है। जेसा की हम

सब जानते हैं कि नकसली समसया लगभग तीन दशक पुरानी है, हालांकि गृह मंत्री महादय ने कहा कि लगातार इस तरह की धटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन खुद उन्होंने बताया है कि बिहार और आंधप्रदेश में वामपंथी उग्रवादियों का जो कंसन्ट्रेशन हे, वह बरकरार है। यह समस्या आई है मध्य प्रदेश के एक मंत्री की हतया के बाद। लेखीराम कावरे उनका नाम था। मध्य प्रदेश को आमतौर पर शांति का टापू कहा जाता है। हालांकि वहां नक्सली हिंसा धीरे-धीरे पैल रही थी लेकिन ऐसी बड़ी धटना या बड़ा हादसा आज तक कभी नहीं हुआ था।एक मंत्री की हत्या हो गई और उसके बाद राज्य सरकार की तरु से अख्बारों में अनधिकृत बयान आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उस बयान की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्शित करना चाहूंबगा। एक अखबार में खबर छापा है कि केनद्र सरकार पिछले दो वर्शों से मध्य प्रदेश की नक्सली हिंसा के संदर्भ में उपेक्षा कर रही है। और तो और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए 650 करोड़ रूपए का जो एक्शन प्लान दिया गया था, उसे भी केन्द्र सरकार ने नकार दिया है। माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया है कि विभिन्न राज्यों के एक्शन प्लान के लिए जो पैसे की डिमांड आई है उसको प्लानिंग कमिशन के पास रेकमेंड किया गया है। तो वास्तविक स्थिति क्या है, इसे स्पष्ट किए जाए? क्योंकि इस दुर्धटना के बाद वहं पर अखबारों में खबरं आ रही है और वहां के गृह मंत्री बाकायादा ऑफीसियली बयान दे रहे है कि केन्द्र सरकार की तरु से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो पहले माननीय गृह मंत्री इस संदर्भ में कुछ बताएं गृह मंत्री जी ने उक्त बात का खुलासा करते हुए आगे यह बताया है कि वहां के गृह मंत्री श्री नन्द कुमार पटेल ने कहा है कि सन् 1998 के अंतिम माह में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की नक्सली समस्या के उन्मूलन हेतु 615 करोड़ रुपए की एक समेकित काय योजना तैयार करके गृह मंत्री के पास भजी थी। कार्य योजना में पुलिस विभाग को 110 करोड़ रुपया देने की योजना भी शामिल है, किन्तु दुख की बात यह है कि आज तक केन्द्र सरकार से उपरोक्त स्वीकृति नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री महोदय बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा बंदोबस्त के खर्च का 50 परसेंट, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सरकार अपने ऊपर उठा रही है परंतु वहां के गृह मंत्री का कहना है कि 1 अप्रैल, 1996 से सुरक्षा व्यवस्था पर हुए व्यय की 50 फीसदी राशि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया है ।परंतु 1996 से 1999 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर राज्य सरकार ने लगभग एक अरब रुपये के आस-पास खर्च किया है किंतु अभी तक उस खर्च की 50 फीसदी राशि केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को नहीं भेजी है । यह मध्य प्रदेश की ताजा स्थिति है और ये बातें उनकी हत्या के बाद निकल कर आ रही हैं । उनकी हत्या के बाद भी घटनाएं जारी हैं, हत्याएं

हो रही हैं । मध्य प्रदेश के एक सांसद के घर को उड़ा दिया गया, अमरावती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को उड़ा दिया गया, बम ब्लास्ट करके । छोटी-छोटी झड़पें आंध्र प्रदेश में जारी हैं । सौभाग्यवश से बिहार अभी शांत है । गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, ये तीन जिलें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और यहां नक्सली उग्रवादियों का अच्छा-खासा प्रभाव है । महाराष्ट्र पुलिस ने अपने स्तर पर जो व्यवस्था की है उसका नतीजा यह है कि वहां अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है । परंतु लगभग पंद्रह दिन पहले गढ़चिरौली से मैं आधी रात को करीब बारह बजे के आसपास लौट रहा था और मुझे वहां के लोगों ने बताया कि यह नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, आप मत जाइए, परंतु मैंने कहा कि मुझे नागपुर जाना है, सुबह हमारी मीटिंग है और मैं लौटा भी । यह प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी गढ़चिरौली के आम लोगों के बीच नक्सली हिंसा का भय है, आतंक है, वे परेशान हैं, घबराए हुए हैं । यह बात और है कि वहां कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, कोई हादसा नहीं हो रहा है । यह अपने आप में एक संयोग है, सौभाग्य है । मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ऐक्शन प्लान के लिए कितने पैसे की डिमाण्ड की गई है, जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है । जब शिवसेना-बी.जे.पी. की सरकार थी तब उस समय यहां पर चर्चा हुई थी, जिसमें यह बात निकलकर आई थी कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ डिमाण्ड भेजी है, जबकि आज के बयान में यह बात उजागर हुई है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और संभवतः उड़ीसा, इन तीन राज्यों की तरफ से ऐक्शन प्लान के लिए प्रस्ताव आए हैं और इन प्रस्तावों को प्लानिंग कमीशन के पास भेजा गया है । लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक किसी स्पेशल पैकेज की डिमांड की है या नहीं ?

आंध्र प्रदेश और बिहार की बात खुद गृह मंत्री ने स्वीकार की है मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इनकी जड़ में क्या है ? पी.डबल्यू.जी. के बारे में बताया जाता है कि वह आंध्र प्रदेश में बैन है, लेकिन मध्य प्रदेश में बैन नहीं है । बिहार में पी.डबल्यू.जी. पहुंच चुका है लेकिन वहां भी संभवतः वह बैन नहीं है जबकि वहां एम.सी.सी. बैन है, आउटलेट है । पी.डबल्यू.जी. जैसे उग्रवादी संगठनों को एक राज्य में बैन किया जाता है तो बाकी राज्यों में बैन क्यों नहीं किया जाता है ? लखीराम कांवरे जी ने संभवतः स्वयं अपने मुख्य मंत्री से इसकी डिमांड उठाई थी लेकिन श्री दिग्विजय सिंह जी ने अभी तक पी.डबल्यू.जी. को इस हत्या के बाद भी बैन नहीं किया है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि बैन करने का मामला केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले तो अच्छा रहेगा । मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पी.डबल्यू.जी., एम.सी.सी. तथा इस तरह के

जो अन्य खतरनाक उग्रवादी संगठन हैं उनकी एक, सूची केंद्र सरकार खुद जारी करे और उन्हें बैन संगठनों की सूची में शामिल करके दे । मैंने पूछा था कि आखिर इसकी जड़ में क्या है ? इसके पीछे जो रीजन मुझे दिख रहा है वह यह है कि बिहार में जहां नक्सली हिंसा है वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासी नहीं रह रहे हैं । मध्य बिहार, जहानाबाद, गया, भोजपुर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासी नहीं रहते लेकिन वहां नक्सल हिंसा जबर्दस्त तरीके से प्रभावशाली है और घटनाएं होती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र के जिन जिलों में हिंसा भड़की या भड़क रही है या नक्सली संगठन सक्रिय हुए, ये सारे जिले आदिवासी जिले माने जाते हैं । निश्चित तौर पर इसके दोनों जगहों में अलग-अलग कारण होंगे । निश्चित तौर पर दोनों जगहों में अलग अलग कारण होंगे । यह कहा जाता है कि बिहार में हमेशा जातीय संघर्ष इसका सब से बड़ा कारण है । मगर आदिवासी क्षेत्रों में क्या कारण है ? जातीय संघर्ष वहां बहुत बड़ा कारण है तो इन क्षेत्रों में क्या कारण है ? इन कारणों की सही ढंग से तलाश हो रही है ? इन कारणों की समीक्षा हो रही है ? क्या इन कारणों को दूर करने के लिए सचमुच में कोई टाइमबाऊंड प्रोग्राम बनाया जा रहा है ? एक चर्चा हमेशा आती है जब कभी कोई नक्सली हिंसा होती है जैसे कि अभी लिखी राम कावड़े की हत्या हुई, यह बात निकल कर आई कि उस क्षेत्र में कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, टेलीफोन का सिस्टम नहीं है, दूरसंचार की व्यवस्था नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, अगर कहीं पुलिस स्टेशन हैं तो वहां पुलिस कर्मी नहीं हैं, वहां पर जितने कांस्टेबल होने चाहियें, उतने नहीं हैं । महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, बिहार की तुलना में मध्य प्रदेश की तुलना में पुलिस स्टेशनों में नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में उतने पुलिस कर्मचारी नहीं हैं । मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था पूरे देश में हो सकती है कि जितने भी नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले । ठीक है कि राज्य सरकारों के अधिकारों में यह इंटरफियरेंस हो सकता है लेकिन नक्सली हिंसा जैसे कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक नेशनल कंसर्न है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, एक राष्ट्रीय प्रश्न है, एक राष्ट्रीय समस्या है । इस राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए केन्द्र सरकार खुद इन राज्यों में जहां जहां नक्सली हिंसा का प्रभाव है इनफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए एक समेकित योजना पर विचार करे और राज्य सरकारों के ऊपर न छोड़े । सब से बड़ा संकट यह है कि जब कभी राज्य सरकारों के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है तो अलग अलग राज्य सरकारें इसको अलग अलग ढंग से लेती हैं । कुछ राज्य सरकारें ज्यादा गम्भीरता से लेती हैं, उन राज्यों में नियंत्रण किया जा रहा है लेकिन जिन राज्यों में

नक्सली हिंसा गम्भीरता से नहीं ली जा रही है उन राज्यों में राज्य सरकारों के फेलयर की वजह से नक्सली हिंसा बढ़ती जा रही है । राज्य सरकार के फेलयर पर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा । हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर आई, भोपाल से एक रिपोर्टर ने बताया -

> "The tribal-dominated Balaghat district has been the Lub of Naxalite activities in Madhya Pradesh for over a decade. The steady growth of the influence of naxalities in the tribal areas of the State is a stark pointer to the fact that despite concerted efforts, the Madhya Pradesh police are finding it extremely difficult to retard the growth of naxalism in areas bordering A.P. and Maharashtra."

इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वहां पर मध्य प्रदेश में उन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जो पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशनों के पास जो हथियार हैं जो वेपंस हैं, उन वेपंस से सौ गुना ज्यादा सक्षम, ताकतवर, स्ट्रांग हथियार नक्सलियों के पास हैं । एक बार अगर कोई नक्सली संगठन अटैक करना चाहे तो पुलिसकर्मी वहां रह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइट बैक नहीं कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में मेरा माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध होगा इन नक्सली प्रभावी क्षेत्रों में पुलिस के पूरे इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना चाहिये । निश्चित तौर पर आर्म्ड फोर्सेज़ वगैरह दिये जाते रहे हैं लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ली जा सकती है । जो कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, माननीय गृह मंत्री महोदय ने ज्वाइंट टास्क फोर्स की बात बताई थी, इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल इस विषय पर जब चर्चा हुई थी तो बताया था कि तमाम नक्सली प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मिला कर के ज्वाइंट टास्क फोर्स बना रहे हैं । ज्वाइंट टास्क फोर्स के पास, कोआर्डिनेशन कमेटी के पास क्या किसी तरह का टाइमबाऊंड प्रोग्राम दिया गया कि आपको एक पर्टिकुलर समय में नक्सली हिंसा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेना है । क्या कोई लक्ष्य दिया गया है, अगर लक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो हम सचमुच कामयाबी तक नही पहुंच पाएंगे और काम जिस प्रकार से होना चाहिये इस लड़ाई में नक्सली हिंसा और उग्रवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प, जो अभियान है, यदि हम उसमें सफलता चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक टाइमबाऊंड प्रोग्राम तय करना पड़ेगा तब कहीं जा कर के नक्सली हिंसा पर काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है । माननीय गृह मंत्री महोदय से दो तीन छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं । इस समय पूरे देश में कितने नक्सली संगठन हैं ? उन संगठनों में कितने बैन किये जा चुके हैं और कितने बैन नहीं हैं ? हमारे देश में

पिछले तीन दशकों में न सही, पिछले एक दशक में अगर बता सकें तो बताएं कि नक्सली संगठनों के हमलों से, जो नक्सली हिंसा होती है, उनमें कितने लोगों की हत्या हो चुकी है और उनमें से कितने सिविलयन, कितने पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, कितने अधिकारी और कितने पुलिस कांस्टेबल थे ?फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नक्सली संगठनों के जवाब में जो काउंटर इन्सरजेंसी ग्रुप्स तैयार होते हैं जैसे बिहार में रणवीर सेना डेवलप हो गयी है और रणवीर सेना अपने आप में नक्सली संगठनों का जवाब है तो इस तरह के कितने काउंटर इन्सरजेंसी ग्रुप्स हमारे यहां हैं? बिहार में रणवीर सेना सामने दिखती है लेकिन रणवीर सेना की तरह और भी कई सेनाएं हैं। वहां पर कई निजी सेनाएं हैं। इन सेनाओं की ताजा स्थिति क्या है? जैसे रणवीर सेना तो बैनड है। लेकिन बाकी सेनाओं की क्या स्थिति है? क्या उन्हें भी बैन किया गया है? क्या आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस तरह के काउंटर इन्सरजेंसी ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं? क्या इनको तैयार होने से पहले रोका जा रहा है? अगर तैयार हुए हैं तो इनको रोकने के लिए, इनको बैन करने के लिए कोई व्यवस्था हमारे यहां हुई है?

नक्सली हिंसा पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस महत्वपूर्ण बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनका, नक्सली संगठनों का जो मूल तत्व, जो मूल सिद्धांत है वह मार्क्सिज्म है, वह वामपंथी विचारधारा है। मैं बगैर किसी को प्रोवोक किए यह जानना चाहता हूं कि इस देश में राजनीतिक दर्जा प्राप्त कर चुके जो वामपंथी दल हैं उन दलों से क्या इन नक्सली संगठनों का कभी कोई नाता रहा है और इस नाते को साबित करने के लिए क्या हमारे पास कोई सबूत है? क्या हम साबित कर सकते हैं कि जो वामपंथी संगठन हमारे देश में राजनीतिक दर्जे को प्राप्त कर चुके हैं उन संगठनों के कुछ अधिकारी, कुछ पदाधिकारी, कुछ आफिस बेयरर्स या कुछ एम.पी.ज., कुछ एम.एल.एज. इस तरह के नक्सली संगठनों से कुछ रिश्ता रखते हैं? इस अनैतिक संबंध का अगर कोई सबूत हो तो माननीय मंत्री जी बताएं।

संक्षेप में, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी केंद्रीय सरकार के पास ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि इस देश से नक्सली हिंसा को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। अगर कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पर कोआर्डिनेशन कमेटी में जो चीफ सेक्रेट्री लेविल की कमेटी बनायी गयी है, उस कमेटी से ज्यादा जरूरी यह है कि पोलिटिकल लेविल पर, चीफ मिनिस्टर्स की लेविल पर जो टास्क फोर्स बनायी गयी है उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाए, उसकी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाएं ताकि नक्सली हिंसा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : किस बात का प्वाइंट आफ आर्डर?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : इसी पर प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : अंडर विच रूल? कौन-से रूल के तहत आप प्वाइंट आफ आर्डर कर रहे हैं?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : यह किस दिशा में बहस हो रही है यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : नहीं, There is no point of order ...*(Interruptions)*... Now, Shri Suresh Pachouri ....

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: नक्सली मूवमेंट या नक्सली एक्टिविटीज इस रिपोर्ट में कहीं नहीं है जो गृह मंत्री ने यहां रखी है ...

Mr. Chairman : Nothing will go on record. He is speaking without permission.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : **

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, नक्सल उग्रवाद और आंदोलन के विषय में गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

इस नक्सल आंदोलन और उग्रवाद का प्रभाव प्रमुख रूप से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में काफी ज्यादा है। इस नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए इन राज्यों के द्वारा एकीकृत कार्य योजना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गयी है। मैं जिस प्रदेश मध्य प्रदेश से आता हूं उसमे भी नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए जो एकीकृत कार्य योजना केंद्रीय सरकार के पास प्रस्तुत की है वह 614.94 करोड़ रुपए की है। जो अलग-अलग मद में पैसे मांगे हैं सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए उसमें 98.76 करोड़ रुपए, सड़क नेटवर्क को सबल बनाने के लिए हैं, 183.34 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के लिए, न्यूनतम बेसिक सेवाओं के लिए 317.84 करोड़ रुपए और जनजागरण अभियान के लिए 15 करोड़ रुपए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस कार्य योजना के अंतर्गत 614.94 करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार से मांगे गए हैं।

---

*Not recorded

जब हम स्वीकार कर रहे हैं कि यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है तो जिन राज्यों में नक्सल आंदोलन वहां के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, इस उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों को जो अपेक्षित वित्तीय मदद मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए वह न दिया जाना भी उतना ही चिंता का विषय है जितना कि गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नक्सल आंदोलन के प्रति चिंता जाहिर की है। मान्यवर, जिन राज्यों में नक्सली उग्रवाद पनप रहा है, उन राज्यों की पुलिस के पास न तो आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हैं और न पर्याप्त प्रशिक्षण हैं जिस से कि वे नक्सलियों से निपट सके। मध्य प्रदश में भी यही स्थिति है। वहां नक्सली उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के पास न तो आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हैं और न उन्हें इन लेफटविंग आंतकवादियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है। इस के लिए राज्य सरकार द्वारा की गयी मांग की पूति भी नहीं की गयी है। जिन खेत्रों में नक्सलवादी आंतक मचाए हुए हैं, खास तौर से उन थानों में पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। खास तौर से म.प्र. के मण्डला, बालाघाट, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा में जोकि आतंकवाद से पीड़ित जिले हैं, वहां पुलिस-कर्मियों की प्रति थाने औसतन संख्या 15-20 के बीच में है जोकि नकसली उग्रवाद से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। एक तरफ तो उन के पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्रनहीं हैं, दूसरी तरफ उन्हे समुचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। यह मेरे प्रदेश की स्थिति है और मैं आप के माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक स्पेशल ऑस्क फोर्स का गठन किया जाए जो कि इस समस्या का ठीक से सामना कर सके ।

मान्यवर, जहां सड़कों के सुधार की बात है, नक्सलवादी उग्रवाद उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां मौलिक दृष्टि से रास्ते उतार चढ़ाव वाले और धने जंगल कर दिये हैं। इसलिए इनकी गतिविधियो को रोकने के लिए आवश्यक है कि वहां सउकों का निर्माण और भौगोलिक दृष्टि से समतलीकरण कर दिया जाए। मान्यवर इस कार्य के लिए भी इन राज्य सरकारों ,द्वारा पैसे की मांग इस मद के अंतर्गत की गयी है जिस की मध्य प्रदेश में अनुमानित लागत 165 करोड़ आंकी गयी है जो कि अभी तक स्वीकृत होकर राज्य सरकार को नहीं मिल पाई है।

मान्यवर, जन-जाग्रति अभियान के तहत जनता के कल्याण संबंधी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों की जानकारी लोगों को देने के लिए जरूरी है कि इस अभियान में सभी कीभागीदारी की जाए। उसके लिए भी मांगी गयी राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने स्वय अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य ऐसे हैं जिन की

कार्य-योजना प्रापत हो गई है और योजना विभाग को उन की संसतुति के साथ में है। के साथ भेजी है।मैं जानना चाहुंगा कि वहां कितना समय लगेगा क्योंकि जितना समय अधिक लग रहा है उतनी ही नक्सलवादी गतिविधियां उन राज्यों में बढ़तीजा रही हैं। तो आखिर हम जिस नक्सली आतंकवाद पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, ये मैं जानना चाहूंगा? मान्यवर मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नक्सलवादी गतिविधियां अन्य राज्यों में भी काफी बढ़ती जा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार के पास इस एकीकृत योजना के सिवाय और क्या योजना है? माननीय मंत्री जी अब अपना उत्तर दें तो इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें। साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों की संख्या कम होती जा रही है। उस पर अंकुश लगा है। मान्यवर, यह अपने आप में एक विरोधाभास वाला व्यक्तव्य है। महोदय, मैं जिस प्रदेश से आया हूं अभी हाल ही में उस प्रदेश के परिवहन मंत्री की दर्दनाक हत्या जिस ढंग से की गयी वह अपने आप में केवल चौंकाने वाली दुखद घटना है बल्कि रोंगटे खड़े कर देनेवाली भी है। इस हत्या की घटना से एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हम कानून-व्यवस्था की स्थति पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या उन जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा कर सकते हैं जोकि नक्सलवादी गतिविधियों के बारे में अपनी आपाज विधान सभा और संसद में उठाते हैं।

जब हम जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो आम इंसान की संरखा इन नकसलवादी उग्रवाद से कैसे कर पाएंगे? यह अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। गृह मंत्रालय की पहले से 15 जून, 1998 को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आन्ध्र प्रदेश में बुलाई गई थी। इस बैठक में जो निष्कर्ष निकले थे, जो अनुशंसा उस बैठक मेंकी गयी थी उस निष्कर्ष पर उस अनुशंसा पर क्या कार्यवाई की गई? जो नतीजे निकले उन पर अमल किया गया या नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से इस पर स्पष्ट जानकारी चाहूंगा।

महोदय, योजना आयोग से जिस एकीकृत कार्य योजना के तहत मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ने धनराशि की माग की है, वह कितने समय के अंदर योजना आयोग से मिल जायेगी ? अब जबकि हम यहां नक्सलवादी उग्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं, नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो क्या गृह मंत्रालय अपनी तरफ से अपनी संस्तुति कर पहल करेगा ताकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर योजना आयोग इस कार्य-योजना का पैसा राज्यों को मिल जाए ? इसके साथ हीएक सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में अन्य राज्यों से पैसे की मांग की गई थी,

जिसमें मध्य प्रदेश को पांच करोड़ रुपया दिया गया, जो कि अन्य राज्यों से कम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश को दस करोड़ रुपया दिया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के लिए भी यह राशि कम है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो बिल्कुल है ही । तो क्या गृह मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करेगा कि मध्य प्रदेश हेतु इस राशि में वृद्धि की जाए।

महोदय, अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां के परिवहन मंत्री लिखी राम कावरे की दुखद हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिलकर नक्सलवादी उग्रवाद के विषय में चर्चा की थी और इसके लिए एकीकृत कार्य योजना के तहत अविलम्ब पैसा स्वीकार करने की मांग की थी ? क्या गृह मंत्री जी इस बारे में कुछ ब्यौरा देंगे क्यों कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनसे भी बात की थी और प्रधानमंत्री जी से भी बात की थी ? मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बहुल इलाके में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए वरीयता और प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश ने इस कार्य -योजना के लिए जिस राशि की मांग की है, क्या उसको कुछ राशि अविलंब दी जायेगी ? महोदय, ऐसा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं । धन्यवाद।

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir.The Calling Attention motion was given to highlight the Naxalite menace in the country. However, I am sorry to find repeated mention of "Left-wing extremism" in the statement given by the Home Minister. I do not know the reason why he selected that particular phrase.

Secondly, Sir, everybody knows that Naxalism has been contained in the land of its origin because correct socio-economic measures were taken and radical land reforms were implemented in that particular State. Therefore, the movement is no longer there in West Bengal. Why it is there in all other States is a point for consideration by the Home Minister of the country.

Thirdly, Sir, what triggered our Calling Attention motion was the gruesome murder of the Minister of Transport of Madhya Pradesh. However, unfortunately, I do not find a mention of this particular thing in the statement of the Home Minister. Why? I do not know. The murder was gruesome. It was maniacal. It was brutal and ghastly. We condemn it with all the vehemence at our command, and we condole his death.

However, this should not be looked at as an isolated incident because in the chit left at the site of the murder, it was stated: "Karimnagar *ka*

badla." As you all know, Karimnagar is a Place in Andhra Pradesh, where some encounters had taken Place and three of their people were killed. I come from Andhra Pradesh. Therefore, my emphasis will be more on Andhra Pradesh.

This is obviously a spill-over of the mindless violence in Andhra Pradesh. This has also been made clear by the 'note' that was left there. The so-called Naxal menace is not confined to Andhra Pradesh alone, but has its offshoots in parts of Bihar, Orissa, MP and the border districts of other States also. Its training centres are there in Madhya Pradesh, in Orissa and in Maharashtra. But, unfortunately, those Governments, till recently,0were com Placed about these matters. Now, they too have been tasting the violence by the Naxalites that was witnessed in Andhra Pradesh. That is how they are able to come into contact with the terrorist outfits in other States and even in other countries. These terrorist outfits have been able to secure highly sophisticated weapons. Probably, the weapons that they have are more sophisticated than the ones our Police and military personnel have got. This is one point which I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister. I would like to know what measures have been taken to see that this gun-running, as is taking Place, in other parts of the world, particularly by the LTTE and what is obtaining in the North-East, does not spread here.

Every year, during the past couple of decades, hundreds of people are killed. Many of them are political leaders, MPs, MLAs, Mandal Chiefs, top police officials and even innocent people. Huge Government and private property is also destroyed. I would like to give you a few statistics for this year -- 1999 -- and the last decade. The number of civilians killed in Andhra Pradesh during the last one year is 115. The statement says that the police are the main target. But as we see, innocent civilians are also the target. I would like to tell the hon. Minister that only 35 police personnel were killed. I know top police officials were also killed during the last three or four years. Three I.P.S. officers were also killed. Fortythree buses, eight telephone exchanges and 508 other public property were destroyed. The total loss of property was valued at Rs.8/- crores. This is the figure given by the Andhra Pradesh Government. During the last decade, the extremists killed 1,715 civilians, 344 police personnel and 3 I.P.S. officers. Other property destroyed were mentioned as 2,699. These are the figures as per the Government record relating to the last one year and the last one decade.

This war of attrition is going on, with nobody winning. This movement had started with some sort of ideological revolution. Romanticism of, I would say, individual annihilation of class enemy or grossly defective political deviation attracted some educated youths. That generation was killed or that generation got demoralised. Now, it has got totally degenerated into gang of lumpens, unsocial, unemployed, youths and desperate mafia. That is why we see the movement getting divided into groups of inter-gang killings and rivalries. It is all because of poverty and unemployment. Who is responsible for their poverty? Who is responsible for their unemployment? Who is responsible for this desperation of the youths in various States? The Government should clearly bear this responsibility. That is what I feel.

The Government's understanding of its origin, the reasons for its sustenance, is very flawed and inconsistent. Sometimes, it claims it is a law and order problem to be dealt with very sternly. At other times, it says it is connected with socio-political issues. This is the statement issued by political leaders. Therefore, the Governments have been adopting a carrot-and-stick policy, offering clemency, huge moneys, offer of rehabilitation, sending emissaries, etc. At other times, the Government resorts to outlawing the party and its affiliates and its organisations. Then they organise fake encounters attracting, in the process, a wide and heinous counter-violence. I would like to draw the attention of the hon. Minister to some of these incidents of fake encounters, which very highly honoured intellectuals of the State have condemned. I do not have to say anything about the encounters. If there are encounters, it is all right. But a fake encounter is very bad. The State cannot be an investigator, a prosecutor and a judge at the same time and give these powers to the Police in the State.

The problem is left to the stupid law and order agencies to be solved ultimately with the slogan, "bump them off". This is the phrase used in Andhra Pradesh. The breeding ground is poverty, gross uneven distribution of wealth, neglected land reforms, socio-economic exploitation of the downtrodden, neglected tribals; and the problem of huge unemployment of the educted as well as the unlettered. These are the sections which are giving life and sustenance to this movement. Precious little is being done to tackle this issue, even though it does take some time. No master plans are drawn up. I would like to know what guidance the Central Government has been giving to the States to tackle these basic problems which are giving sustenance to this particular movement. No master plans are drawn up - all the while

deluded with "Information Technology" reforms of the first and the second generation, grandoise but short-sighted, plans. Sir, unless these basic issues are attended to, these rituals of offering condolences to the dead, futile discussions in the Assembles and Parliament and offering *ex-gratia* payment, seats to the kith and kin of the deceased, cannot and will not solve the problem. We have to tackle the basic problem which is responsible for the rise and growth of naxalism in this country. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : Mr. Chairman, Sir, I am very happy at the way in which Dr. Radhakrishna Murthy, our colleague from Andhra Pradesh, has explained various aspects of this issue. Sir, you are also aware about the effect of this problem in the State of Andhra Pradesh. My suggestion to the Government and to the political parties is that this is a political issue, I don't consider it as a social issue, I don't consider it as a law and order issue, I don't consider it as any other issue. It is a political issue. The philosophy of this is simple. Some Members said, "Left Wing Extremism" We can delete it also because we have to do justice to the issue and to the victims and to the problem also. The policy they have is "Power will come through the barrel of the gun. We do not believe in the ballot. We believe in personal annihilation of class enemies or whatever it is." This is their basic philosophy. Unless the country and the political spectrum across the country understands this basic philosophy of these organisations, this problem is not going to be solved. You can call these organisations as extremist or naxalites or Maoist group or whatever it is, we need not quarrel over the terminology of the description of these groups. There can be some sort of a broad agreement on that. But the basic issue is this. Any number of Governments I have seen, they say, they are willing to have a dialogue. They invite them to come to the Jana Jeevan Sravanti. They give a call. They are ridiculed. Those people say, "We are in the Jana Jeevan Sravanti. You are foolish. You are not in the Jana Jeevan Sravanti. So, you come to our line." That is what they say openly and they declare it. Sir, they are indulging in mindless violence, killing every section of the society, members of the BJP, Congress Party, CPI, CPM and even CPI (ML), the so-called extremist group, different shades, every one of them is becoming their target. The fear is such that political parties -- that is why I have said I am very happy about what Dr. Radhakrishna Murthy spoke in the House today - political personalities, elected people's representatives, all are afraid even to open their mouth because of these killings, because of their being targeted by Naxalites. They

say, "These are informers." Who is an informer? They say, " 'X' is an informer. So, we are finishing him." As has been asked by Mr. Sanjay Nirupam and other friends, I would have been happy if the hon. Home Minister had told us about total effect of this movement, the number of killings, the number of property destroyed and incidents that have taken Place in each and every State, particularly, in these five States, Andhra Pradesh, Orissa, Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka. These are the States which are affected.

And, in some States, these people are taking shelter. They hit here and run there. There is no coordination between the two State Governments. That is why this problem is coming. Now, a Minister, a Cabinet Minister--a tribal-- is killed in Madhya Pradesh. In Andhra Pradesh, among the victims, there are tribals, there are Scheduled Caste people, there are women, there are children. They have set fire to a train, the Kakatiya Express, which resulted in the killing of 48 innocent passengers. I do not go into the categorisation of the passengers. Most of them were, unfortunately, minorities in that train. They were killed for no fault of theirs. They were all burnt to death. After so much time, they issued a statement saying, "We regret what we have done". The other day, they have set fire to a family where there was a child. The woman was crying, "My child is only six months old. Please allow me to take some blankets." They did not allow her. It was cold. Finally, that child also lost its life. Mindless violence! Unfortunately, some political parties in my State adopt different stands at different times. When they are in power, they take one line; when they go to the opposition, they take a different line. And the broad policy of governments there is, "Condolence for the dead and compensation for the surviving victims". Can it be a policy? The different political parties and we, the people's representatives, have to take a view on this issue. It is a big challenge to our democratic system. It is a challenge to our parliamentary democracy. We do not believe in killing people. 'Bumping off' is no solution. It cannot be. But the fact of the matter is that those people take to arms! They move openly! They collect money forcefully! And they target people and kill them! They do not want any other political activity, function, in the respective areas, zones, of their influence. That is the basic issue. Sometimes, the BJP becomes the target; sometimes, the CPM becomes the target. They have killed so many people. A Member from the other House, the Lok Sabha, Mr. Subbarami Reddy, was done to death. Only two months back--the latest--one of the MLAs, who was a candidate in the

Sirpur Kagaznagar--Mr. Purushottama Rao, was killed, for no fault of his. Even the house of one of our Members here in this House, Mr. Ramachandra Reddy--I hope he is here--was blasted. Nobody is in a position to come out openly. Everybody expresses condolence. Nobody is willing to make condemnation. I am not talking of any particular party or particular individuals. Because of the psychological fear they are creating in the minds of people there, they continue this without any stop. Railway stations, police stations, Mandal Praja Parishad offices, banks, rural banks, particularly, railway signalling equipment and political personalities' houses--they are all their targets. Nobody is in a position to give protection to them because they adopt the 'hit and run' policy. They create a fear psychosis. They have sophisticated weapons, more sophisticated than those of the regular police! There is fear in the mind of the police also because political leadership cannot go to their rescue. After all, the policeman is there for a salary. It is not because of any ideological commitment. He is there for his livelihood. Sometimes, people find fault with them also. DIGs, IGs, Superintendents of Police, different political parties' leaders, other leaders of Telugu Desam and Congress--Duggirala Venkatrao; Hayagrivacharya, freedom fighter from the Congress Party, who was a former Minister; I can give a number of names--people are bing killed without any meaning.

I have my differences with the Communist Party. But the Communist Party, my understanding is, want to fight for a particular cause in a particular method, in a particular way. They are trying to, they want to, come to power. Fine, no problem. The BJP has got a different ideology, a different philosophy. We do not agree with each other. But we respect each other because we are working for the betterment of the people in a particular fashion which is to our liking or commitment. But, unfortunately, these people have taken a wrong course and they are purusing it mindlessly without any result. With the result, what do I find? I became an MLA in 1978. In the initial days, when there was some encounter, when there was some attack on extremists, I myself and other Members used to raise it in the House and condemn the police left and right. "Why are you doing it? Why are you affecting the civil liberties of the people?". But, unfortunately, now they have come to a stage where they are killing everybody. Whenever an extremist is killed, some people shout saying, "Why is there an attack on civil liberties?". But, when civilians, innocent people, are killed, no voice is raised. I do not know what sort of civil liberties movement it is. I am not able to understand.

We--the BJP, the CPM, the Congress and other parties--have organised joint meetings also.

But what I suggest through this august House is that a strong public opinion has to be created against this very philosophy itself. If they have confidence in their ideology and philosophy, they must also come to the public, they must also go around the people, they must educate the people and they must win over the hearts of the people. They can come to power and they can rule the country also. After all, we have seen mighty empires and great leaders in this country. They were defeated in the battle. This democracy is still vibrant and capable of electing and dethroning different regimes. But unfortunately, these people do not believe in this philosophy. They are sacrificing thousands of youngsters in this mindless philosophy, many boys from the universities, from the colleges, without understanding the implications and an indepth philosophy of this organisation, are drawn to this organisation. They are also laying their precious lives; genius guys, youngsters, engineers, medical students, are joining the movement without realising the fact that there is no way for them to come out of this movement, because the moment they come out of the movement, they are also becoming targets, and then they are being done away with by these organisations. So, this is the basic issue. It is a political philosophy, it is a political ideology which cannot be acceptable to a democratic society. So, all political parties should come together to fight these organisations politically, to corner these people, and then expose their designs. My hon. friend, Dr. Radhakrishna Murty, has said that now the movement has gone into the hands of lumpen elements, I agree to disagree. When I was in jail during emergency, some of the extremists were also arrested at that time because of emergency. We were discussing these things inside the jail, and then we used to say that though their philosophy is very good, the line of approach is wrong. That used to be our thinking. But today you find these people indulging in looting, arson, setting the houses on fire, killing people inside their houses, without any reason, and setting on fire the trains. How can any philosophy, any ideology allow such actions on the part of any organisations? And then they issue statements justifying their actions. Sometimes, they say that since so and so was the enemy of the people, that is why they have done away with him. That means they are sitting as prosecutors, and they are the hanging authorities. This is what is happening, not only in Andhra Pradesh, but also in parts of Karnataka, parts of Maharashtra, parts of Madhya Pradesh and parts of

Orissa. At the same time, I am not asking the Government to keep quiet on the social front, on the developmental front. The developmental activities have to take placed irrespective of whether there is extremist problem or not. Some of my friends have told me that this problem has gone out of West Bengal, thanks to whatever the Government of West Bengal has done in this respect. But, at the same time, that may be on account of the political line or the approach of the State Government there. But Orissa is much more backward and poor. Nothing is happening there. In Andhra Pradesh, the areas which are prosperous, which are having three crops per year, even those areas are affected by the extremist violence or the extremist menace. So, I do not agree with the view that this problem is on account of social backwardness or exploitation. After all, all of us, who are sitting here, are the leaders of different political parties. We also believe in fighting exploitation, we believe in fighting corruption, we believe in fighting inequalities in our own way, though we may have differences of opinion, we are committed to them. It is not the monopoly of these people alone. So, getting credibility by doing such things and then giving it a philosophical or ideological colour, is not a correct thing. I suggest to the Home Ministry one thing. The Government has taken an initiative. The hon. Home Minister visited Hyderabad, had a meeting of the five States concerned. But this should be a continuous activity. There has to be a continuous monitoring. Mere supply of firearms or giving some more money alone is not sufficient. This, according to me, is secondary. It is a political fight; so, political parties also should be involved. The Government of India should really take up such issues even in the Chief Ministers conference. I go to the extent of saying that the Government of India, the Home Ministry, should take an initiative even to have a dialogue with different political parties so that we all speak with one voice with regard to the issue of violence, with regard to the issue of killing of people and their annihilation, and then the belief that power comes through the barrel of the gun. All these aspects have to be tackled by all political parties. Till such time we speak with one voice, this will continue, and as I said earlier, we will continue paying condolences for the dead, and compensation for those who survived. I have been seeing it from 1980 onwards, every time, someone dies, someone is killed, there is a mourning, everybody rushes to that place, then afterwards, nothing is being done, nothing is being heard also. That being the case, I request the Home Ministry not only to have a regular interaction with the States and then forcibly

implement the mechanism that they have evolved but also create public opinion, because basically, law and order is a State subject and it is the State Government which practically deals with the situation.

Whatever help they need, that has to be given by the Central Government. But, at the same time, a political will is required; a political commitment is required. This political philosophy has to be fought politically. For that the Government of India should take steps. Is it willing to do it? It should call a meeting of all these people and create enough public opinion. We have a disturbing information that these people have connections with the LTTE; that they have connections with other extremist organisations and that some help is coming from abroad. People say that there is ISI connection also. All this is disturbing. If it is only a social factor, then, there is no need to have any LTTE connection; there is no need to have any connection with the ISI, and there is no need for any international connection for this purpose. That being so, the Government has to be very vigilant . At the end, I would suggest that the Home Ministry of the Government of India should come with a White Paper, giving details of the number of victims at various levels, including.... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, it is already 1 o' clock and eight more Members have given their names to speak. Should we sit during the lunch hour?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Then, everybody should restrict themselves to the clarifications. Now it has become a debate. It is a very important subject, touching the heart of India. There is no doubt about it. I would request the Members to please shorten the questions, or, comments only to the clarifications that they want from the Government, so that we can have other business also.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I will finish in half a minute. I will just complete it because it is not an issue where there is no need, or, no scope for political will. I only request the House to understand the magnitude of the problem and the agony of the people who have become victims of this mindless violence. No amount of sympathy is going to bring back their family members. I myself have seen some of my Party workers, that is, those who have worked with me. They work for 24 hours a day, leaving their

families. Some of the workers of the BJP, the RSS and the ABVP have been done to death without any reason whatsoever, in this mindless violence. So, naturally, we also get agitated. But coming back to these things, I would request the Home Ministry to come out with all the details, so that these details can be put before the people. The people can also be educated. Enough public opinion should be created to isolate this so-called philosophy of mindless violence for personal annihilation. The Government of India should think in these terms. This is my suggestion and this is my request.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): सभापति महोदय, नक्सली गतिविधियों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जोबयान दिया है, उसमें शुरू की पंक्ति में यह है कि देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में वामपंथी उग्रवाद चिन्ता का प्रमुख कारण है

MR. CHAIRMAN: Please seek clarifications only. The Members should seek clarifications only, so that the Minister can reply. If we make it a Short Duration Discussion, then, I think, the whole one hour will be....*(Interruptions)*...

श्री जलालुदीन अंसारी : इस पर तो बोलना है न ।

श्री सभापति : बोलना नहीं है, यह कालिंग अटेंशन है। अगर डिबेट होगी तो वह ढाई घंटे के लिए होती है ।

श्री जलालुदीन अंसारी :सब कोई बोले हैं तो हम क्यों नहीं बोले ।

श्री सभापति : बोलिये लेकिन आप पिनप्वाइंट करें ताकि जवाब मिल जाए।

श्री जलालुदीन अंसारी : इसीलिए मैं सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री सभापति: हां हां, उठाइये।

श्री जलालुदीन अंसारी :सवाल यह है कि वामपंथी उग्रवादी जो संगठन है, दूसरा एक प्रमुख कारण आज के नक्सलवादी उग्रवाद के पीछे है। लेकिन उसी का दूसरा पक्ष मैं बिहार की चर्चा करते हुए आपको बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, नक्सली गतिविधियों को रोकने के नाम पर रणवीर सेना नाम संगठन बना, उसको दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठन कहेंगे या नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जब वह सफाई देंगे तो बताएंगे । इसलिए चाहे वह वामपंथी उग्रवादी संगठन हों या दक्षिणपंथी संगठन हों, इन दोनों के जब तक सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक इस तरह नरसंहार, आतंक,

हत्या की घटनाएं होती रहेंगी। आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या अन्य जगहों पर जो घटनाएं घट रही हैं, इनको रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकारों को भी करनी है और केन्द्र सरकार को भी उसमें भरपूर मदद करनी है। जहां तक नक्सली संगठनों का सवाल है वे गांव के गरीबों को इसलिए भी अपने पक्ष में कर लेते हैं कि उसके कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। इस पर केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है।

पहला कारण है जो भूमि सुधार कानून बनाए गए - लैंड रिफार्म्स ऐक्ट - उनका लागू नहीं किया जाना। अभी-अभी हदबंदी से फाजिल जमीन रखने वाले लोग हमारे बिहार में वहां पर हैं जो नक्सली इलाका कहा जाता है। तो इसका नाजायज फायदा वे लोग उठाते हैं। वे गरीबों को कहते हैं कि जमीन बांटते नहीं हैं इसलिए हथियार उठाओ। केंद्रीय सरकार ने भी पूरे देश के लिए लैंड रिफार्म्स ऐक्ट संविधान में संशोधन करके बनाए हैं और राज्य सरकारों को कहा है कि इनको लागू करो। तो केंद्र सरकार का भी दायित्व है। राज्य सरकारों का तो है ही। उसी तरह से न्यनतम मजदूरी खेत मजदूरों को नहीं मिलती है। यह दिलाने का काम राज्य सरकारों का है। लेकिन केंद्र सरकार को भी ऐसा मिकेनिज्म बनाना चाहिए कि राज्यों के अंदर जो न्यनतम मजदूरी कानून हैं दे लागू हों ताकि उन गरीबों के असंतोष का बेजा फायदा कोई वामपंथी उग्रवादी संगठन या दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठन न उठाये। यह तो उनका दायित्व बनता है। उसी तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। वे इन संगठनों में चले जाते हैं - जिनके पास हथियारबंद गिरोह हैं। वे अपराधकर्मी गिरोहों में चले जाते हैं। वे दंगा-फसाद में शामिल हो जाते हैं। इन बेरोजगार लोगों को रोजगार न दिलाना भी एक कारण है। आज के भी समाज में, जुल्म, अत्याचार, छुआछूत, पक्षपात आदि सामाजिक चीजें अभी भी गांवों के अंदर जारी हैं। इनका भी लाभ ये उग्रवादी संगठन उठाते हैं। इसलिए जो सामाजिक, आर्थिक कारण हैं इन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, यह मैं माननीय मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।दूसरा है कि वोटों के लिए कुछ राजनीतिक दल, वामपंथी उग्रवादी संगठनों का भी इस्तेमाल करते हैं, दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठनों जैसे रणवीर सेना का भी उपयोग करते हैं। मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसकी जानकारी आपको है। बिहार में क्या हो रहा है? अगर नहीं है तो इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। अभी हमको मालूम है कि इसकी जानकारी आपको है। इसलिए मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता हूं। मैं श्री वेंकैया नायडू से सहमत हूं कि दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्यवाही करें और इसके लिए जो जो उचित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कदम उठाने की

आवश्यकता है अगर वे नहीं उठाएंगे तो इस सदन में आप बार बार बहस करते रहेंगे, गृह मंत्री जी बयान देते रहेंगे। लेकिन इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। यह मेरी मजबूत समझ है।

बिहार में इन घटनाओं में बड़े-बड़े जनसंहार हुए हैं। आरोप चले हैं कि एम.सी.सी. ने यह कर दिया। अभी हमारे बिहार में आन्ध्र प्रदेश से वेंकैया जी ने पीपुल्स वार ग्रुप को भेज दिया है ... (व्यवधान) चला आया है भेजा नहीं है। तो वे बिहार पहुंच गए हैं। ये सब मिल करके उन क्षेत्रों में काफी आतंकवादी कार्यवाहियां कर रहे हैं, हत्याएं भी कर रहे हैं। हम इससे भी सहमत हैं कि इस लड़ाई में अमीर ही नहीं गरीब भी मारे जाते हैं। ज्यादा नुक्सान इनसे गरीबों को होता है चाहे वह वामपंथ का उग्रवादी संगठन हो या दक्षिणपंथ का। दोनों के हमले के शिकार गरीब लोग हुआ करते हैं चाहे वे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के हों। बिहार के उदाहरण इसी बात के प्रमाण हैं। माननीय गृह मंत्री जी को इसकी सारी सूचना मौजूद है।

मैं उन नरसंहारों की चर्चा यहां नहीं करूंगा क्योंकि वह मामला हाउस में कई बार उठ चुका है और वह सर्वविदित है । रहा सवाल कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में उग्रवादी संगठन हैं कि नहीं, तो वे मध्य बिहार और उत्तर बिहार में हैं, फिर चाहे वह हजारीबाग का इलाका हो, गिरिडीह हो, चतरा, हो, पलांमू हो या गढ़वा हो । ये आदिवासी क्षेत्र हैं और वहां एम0सी0सी0, पीपुल्स वार ग्रुप के अलावा एक लाल खंडी नक्सलवादी संगठन भी है । यह मैं गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं । तो आदिवासी क्षेत्रों में संथालों के बीच में भी ये संगठन बढ़ रहे हैं । इसलिए जिन 4-5 राज्यों की आप ने चर्चा की है वहां इन का भीषण प्रकोप है। महोदय, जिन तरह से वे संगठन हमला करते हैं उस से स्थानीय पुलिस और प्रशासन त्राहि माम का संदेश देकर अपने को सुरक्षित रखने को तैयार रहता है । इस का कारण यह है कि इन आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधुनिक अस्त्र हैं और हमारी पुलिस के पास वही पुरानी बंदूक है । यही वजह है कि जहां पुलिस पिकिट है, वहां से आतंकवादी संगठन सारे हथियार लेकर चले जाते हैं और पुलिस वाले चुपचाप रह जाते हैं । कहीं-कहीं वे पुलिस-कर्मियों को मारकर उन के हथियार ले जाते हैं । ऐसी बिहार के अंदर अनेक घटनाएं हुई हैं । इसी तरह की घटनाएं ये उग्रवादी संगठन दूसरे राज्यों में भी करते हैं ।

महोदय, आप ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम ने इतना-इतना पैसा अमुक-अमुक राज्य को दिया है, लेकिन इस में बिहार की आप ने चर्चा नहीं की है । आप ने आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दिया है, मैं जानना चाहूंगा कि बिहार

की चर्चा क्यों नहीं की गयी है ? इस के लिए आवश्यक सहायता बिहार को भी दी जानी चाहिए क्योंकि वहां भी रोज पुलिस वालों के हथियार छीने जाते हैं और पुलिस कुछ करने की हालत में नहीं है । उन पुलिस वालों के पास जो हथियार हैं वह उन के आधुनिक हथियारों का मुकाबला करने में नाकाफी हैं ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वामपंथी दलों के इन संगठनों से संबंध हैं । मैं कहता हूं कि संबंध नहीं हैं । मैं इस सदन के माध्यम से उन से कहना चाहता हूं कि उन के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है । वह हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी हत्या करते हैं । पिछले साल ही हमारे एक प्रमुख और उस के बेटे की रात में हत्या कर दी गयी । इसी उग्रवादी संगठन ने बागेश्वर शर्मा और उन के बेटे की हत्या की जो कि हमारी पार्टी के प्रखंड प्रमुख और जन-प्रिय नेता थे । इसलिए सिद्धांत की बात कर के इस समस्या के साथ घालमेल करने की जरूरत नहीं है । हम लोग राजनीतिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर उन के खिलाफ हैं और सरजमीं पर भी उन से लड़ते हैं । इसलिए जिन चीजों की यहां चर्चा की गयी है, उन को करने की आज जरूरत है । आज ग्रामीण जीवन में विकास कार्यों को कर के उन नौजवानों को जीवन की मुख्य धारा में लाकर इन उग्रवादी संगठनों को अलग-थलग करने की आवश्यकता है । सिर्फ दमन से आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए विकास कार्यों के जरिए और जिन बिंदुओं की चर्चा मैं ने की है, उन कदमों को उठाकर और वहां के नौजवानों को मुख्य धारा में लाकर आज चाहे दक्षिण-पंथी उग्रवादी संगठन हो या वामपंथी उग्रवादी संगठन हो - इन दोनों के सामाजिक आधार को समाप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक कदम उठाने होंगे । इस के साथ ही साथ प्रशासनिक कदम भी उठाने होंगे और पुलिस बल को आधुनिक अस्त्रों से लैस करना पड़ेगा । अंत में मुझे यह कहना है कि इसके लिए अपने दलीय लाभ को ध्यान में न रखते हुए इन संगठनों को जो राजनैतिक संरक्षण दिया जाता है, वह संरक्षण न दिया जाए। मैं सभी दलों से यह अनुरोध करुंगा कि वोट के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो आप संरक्षण देते हैं, उसको कृपया बंद कीजिए । अगर आप बंद नहीं करेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ प्रचार करके आप इस समस्या का समाधान कतई नहीं निकाल सकते । मैंने बहुत ही विनम्र और जवाबदेही के साथ, जो बिहार की स्थिति है उसको ध्यान में रखकर, सही तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है । यही वस्तुस्थिति है । जब आप उनको राजनैतिक संरक्षण देना बंद करेंगे तब जाकर सही रास्ता निकलेगा ।

महोदय, यह बात भी ठीक है कि उनके बीच जन चेतना फैलाने की जरूरत है । जहां तक यह लोग अपने आपको तथाकथित मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन इनको

मार्क्सवाद का ज्ञान ही कहां है । यह तो मार्क्सवाद से भटके हुए लोग हैं और उनको मार्क्सवाद से कोई वास्ता नहीं है, जनता से कोई वास्ता नहीं है । यह लोग जनता की भावनाओं का गलत तरीके से उपयोग करके अपने लाभ के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरे तरह के कार्य में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ ।

महोदय, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता । मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी और भारत सरकार इन राज्यों में इन समस्याओं के सही समाधान के लिए, सामाजिक आर्थिक कदमों को उठाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे और प्रशासनिक कदम उठाए । इसके साथ ही मैं राजनैतिक दलों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने वोट के लाभ के लिए ऐसे संगठनों को राजनैतिक संरक्षण न दें और न किसी प्रकार की मदद दें, तभी हम इस समस्या से निपट सकते हैं और कोई सही समाधान निकाल सकते हैं । धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN: If every Member starts speaking for 15 to 17 minutes for seeking clarifications, we cannot finish the Calling Attention before 2 o'clock because the Minister has also to reply. If you confine yourself to two or three minutes, it will be much better and fruitful because you will be able to get the reply.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : सर, समय की पाबंदी में थोड़ी सी ढील कर दीजिएगा । मुझसे पहले बोलने वाले 17 मिनट, 20 मिनट बोले, मेरे लिए 2 मिनट की पाबंदी न कीजिए । यह मेरी आपसे दरखास्त होगी ।

श्री सभापति : ठीक है, ढाई मिनट ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ ।

श्री सभापति : अच्छा, 3 मिनट सही ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, 10 मिनट कर दीजिए।

श्री सभापति : गृह मंत्री जी को जवाब भी देना है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, गृह मंत्री जी ने नक्सलवादी कार्यकलापों के बारे में जो बयान दिया है, उस पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी । इसमें कई प्रांतों की चर्चा संजय निरूपम जी ने की है, जो मंत्री जी के बयान में भी है । मैं केवल अपने आपको

बिहार तक ही सीमित रखूंगी । मेरे पूर्व वक्ता जलालुदीन अंसारी जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातों को कहा है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी । मैं आपको केवल बताना चाहूंगी कि मध्य बिहार में ही नहीं, मध्य बिहार के अलावा रोहतास की जो कैमूर पहाड़ी है, उसमें बड़े पैमाने पर नक्सलवादियों ने, आज से ही नहीं बल्कि काफी शुरू से, अपना स्थान बना रखा है, जो आज भी है और इनको राजनैतिक संरक्षण भी मिला हुआ है, जिनमें तरह तरह के संरक्षण हैं । एक तो वहां पर पुलिस चौकी नहीं है । अगर कोई पुलिस चौकी बिहार में है भी तो वहां पुलिस वालों की यह स्थिति है, जैसे पुराने जमाने में अंग्रेजों के समय में एक पुलिस चौकी में घोड़ा हुआ करता था और पांच कांस्टेबल हुआ करते थे, शायद आज भी वही स्थिति बनी हुई है, घोड़ा तो नहीं है, लेकिन अस्तबल के नाम पर कुछ होगा । मेरा यह कहना है कि उनको मोडर्न इक्युमेंट मिलने चाहिएं, उनके लिए जीप गाड़ी अच्छी कंडीशन वाली होनी चाहिए । लेकिन, बीच बीच में इसकी भी निगरानी होती रहनी चाहिए कि वह जीप गाड़ी कहीं दरोगा जी के काम में तो नहीं आ रही है या हैड कांस्टेबल साहब के ही काम में तो नहीं आ रही है , सचमुच में यह क्राइम कंट्रोल के काम में आ रही है। यह बहुत आवश्यक है और जो पुलिस की टुकड़ियां हों, वे 5-7 लोगों की होने से काम नहीं चलेगा, यह बड़ी टुकड़ियां होनी चाहिए और पुलिस की बहाली जो हो, उसमें थोड़ी निगरानी होनी चाहिए । यह कौन करेगा, यह तो मैं नहीं जानती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जैक्ट है और पुलिस की जो बहाली होती है, उसमें भी बहुत गलत तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हें भी देखना होगा । अब प्रान्तीय सरकारें अगर यह करती हैं तो इसमें केन्द्र सरकार क्या करेगी, यह मैं नहीं जानती, लेकिन स्थिति ऐसी है । रांची, हज़ारीबाग, गिरिडीह, चतरा, पलामू और गढ़वा जिले, ये सब जंगल के और पहाड़ी इलाके हैं और इन सब में एम0सी0सी0 के नाम पर तरह-तरह के क्राइम होते रहते हैं और सचमुच इसमें एम0सी0सी0 वाले इन्वाल्व हैं या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है लेकिन बड़े पैमाने पर निश्चित रूप से इनका भी हाथ है । अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसमें सी0सी0एल0 का एरिया, कोयला अंचल भी आता है, वहां लालपनिया में एक बिजलीघर बना है, वहां तक जाने के लिए करीब 20-25 किलीमीटर की एक सड़क बन रही थी, जिसे आर्मी का एक आरगेनाइजेशन - बॉर्डर रोड आरगेनाइजेशन - बना रहा था, उन्होंने उसके इंजीनियर को ही उठा लिया यह कहकर कि वह पैसे देंगे । जलालुदीन जी ने ठीक कहा कि उनका पेशा हो गया है हर काम में पैसा मांगना । गांव में सड़क बनती है, एम0पी0 लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत सड़क बनती है, उसमें वे चंदा वसूलते हैं, बाकी कोई काम होता है तो उसमें से चंदा वसूलते हैं और काम नहीं करने देते हैं, विकास का काम नहीं करने देते हैं और लोग डर के मारे भाग जाते हैं । तो उन्होंने

बॉर्डर रोड आरगेनाइजेशन के इंजीनियर को किडनेप कर लिया । बॉर्डर रोड वालों ने अपने गनमैन मंगवाए और अपने उन गनमैनों के सहारे, बंदूक के साए में उन्होंने रिकार्ड टाइम में उस सड़क को बना लिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर को एक सप्ताह के अंदर आप रिकवर करके ला दीजिए नहीं तो हम इस ईश्यू को डिफेंस मिनिस्ट्री तक उठाएंगे और सरप्राइसिंगली वह इंजीनियर वापिस आ गया । तो यदि कोई काम करना चाहे, तो हो सकता है । इस घटना का ज़िक्र मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए किया कि इस तरह की बातें वहां हो रही हैं । इसमें एक जो आवश्यकता है, वह है पुलिस फोर्स के मॉरेल को हाई करने की । अब यह तो शायद आपके हाथ में है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, अब आप उसे कैसे चुस्त-दुरुस्त करेंगे यह आप जानें । दूसरा, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट देने की जरूरत है और क्विक मूवमेंट हो, यह बहुत जरूरी है । कहीं अगर कोई वाकया हो जाए, वहां पहुंचने के लिए क्विक मूवमेंट हो, उसके लिए भी उपाय करने होंगे । तीसरी बात है कि जो हमारी पुलिस के जवान हैं, उनका भी थोड़ा मॉरेल हाई होना चाहिए, आज उनका मॉरेल बिल्कुल डाउन है । आज कोई काम करने जाना नहीं चाहता है, कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, आज यह हालत हो गई है ।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी, वह यह है कि गांवों की स्थिति तो आज यह हो गई है कि लोग लाल झंडे की जय करके अपनी जान बचा रहे हैं । माफ कीजिएगा, हमारे साथियों में से बहुतों का लाल झंडा है, मैं आपके झंडे के बारे में इशारा नहीं कर रही हूं । लेकिन वहां आज हालत ऐसी है कि लाल झंडे की जय बोलकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं और वे उनको रेगुलर टैक्स देते हैं, अनाज देते हैं, रुपया देते हैं । सारे इलाके में बिल्कुल एक पैरेलल् गवर्नमेंट चल रही है और बिहार के आधे इलाकों में इस तरह की पैरेलल् गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट का रिट रन नहीं करता है वहां, अगर रन करता है तो मैं नहीं जानती कि वह किस ढंग से रन करता है, उसका कोई दूसरा तरीका है, जिसके बारे में जलालुदीन अंसारी जी ने भी ज़िक्र किया, उसी ढंग से वह पोलिटिकल कनाइवेंस होता होगा ।

इसी तरह, महोदय, एक और जो सबसे चिंताजनक बात हो गई है बॉर्डर एरिया में, क्योंकि हमारा बॉर्डर काफी दूर तक नेपाल और बंगला देश के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, वह यह है कि उल्फा उग्रवादी भी उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, आई.एस.आई. के लोग भी आकर हाथ मिला रहे हैं और ये लोग जाली नोटों का कारोबार भी कर रहे हैं । तो यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और बिहार जैसे शांतिप्रिय स्टेट में, जहां भगवान बुद्ध, महावीर और अनेक सनामधन्य व्यक्ति हुए हैं, उस प्रान्त में यह

स्थिति पैदा हो गई है कि मध्य बिहार में, उत्तर बिहार के सीमावर्ती इलाके में और छुटनापुर के इलाके में आज गांव में कोई व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता है । आज कोई घर से निकले तो वह वापिस आएगा या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है । आज वहां यह स्थिति हो गई है । शाम के बाद वहां लड़कियां घर से निकलती नहीं हैं । कोई परिवार - पति, पत्नी, बच्चे - एक साथ जा नहीं सकता । वापिस आएगा कि या नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, यह स्थिति हो गई है। इस ध्यानाकर्षण के जरिए इन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी कि इस पर केन्द्रीय सरकार समुचित उपाय करे ताकि इस स्थिति में सुधार हो। बिहार में जंगल राज है।

MR. CHAIRMAN : Shri Ramoowalia. I hope, you will restrict yourself to three minutes.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद सभापति महोदय। एक तो मैं राय देता हूं कि इतिहास पिछली घटनाओं का मूल्यांकन होता है और आने वाले समय के लिए तजुर्बा होता है। एक तो बार-बार यह मत कहो कि यह नक्सलाइट वामपंथियों से जुड़े हैं। सभापति जी, यही गलती सिखों के बारे में की गई थी। टेरोरिस्ट मुट्ठी भर थे सभी सिखों को कह दिया कि सभी टेरोरिस्ट हैं। वह भी गलती थी। आज इसको समझने की कोशिश करो कि सिख टेरोरिस्ट शब्द प्रयोग करना गलती हुई। अब वामपंथी नक्सलाइट मत कहो, सिर्फ नक्सलाइट कहो -नम्बर एक। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि.....**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : बड़ी टेक्नीकल बात ढूंढी है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हम तो कोशिश करते है कि फिजूल बात कोई और आदमी करे, हम न करें हमारी यही कोशिश होती है।

दूसरी बात, जनाब, मैं यह कहना चाहता हूं कि टेरोरिज्म नक्सलाइट्स का हो, धार्मिक हो उसमें लूट खसोट, मासूमों व यतीमों का नुकसान करना और नौजवान लड़कियों और बच्चियों का शोषण करना, चाहे यह आई.आर.ए. हो, नक्सलाइट्स हों, खालिस्तानी हों यह होता ही रहा है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इन लोगों की कंसोलिडेशन हो रहा है आइसोलेशन नहीं हो रहा है। अगर आइसोलेशन हो रहा है तो क्या माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि किन-किन बातों में आइसोलेशन हो रहा है? दूसरे, जैसा मैंने पहले कहा कि सभी वामपंथियों को इसमें न माना जाए। इसके बारे में क्या कोई रेडियो, टी0वी0, अखबारों के लिए कोई नीति बनेगी

कि सभी वामपंथी नहीं केवल नक्सलाइट झंडे तले यह गिरोह जुडे हैं। तीसरे, क्या यह सच है कि नक्सलाइट संगठनों में भारी संख्या में जो लोग हैं वह अति गरीब लोग, बे-जमीन लोग, बेरोजगार लोग अमीरों और समृद्ध वर्गों के शोषण के शिकार लोग हैं, या कोई और लोग हैं? चौथे, इन संगठनों का बुनियादी सिद्धांत क्या है? क्या वह बुनियादी सिद्धांत हमारे आम वर्ग के लोग जो अमीर वर्ग में नहीं आते उनको आकर्षित तो नहीं कर रहा है? आखिर यह कैसा सिद्धांत है? क्या कोई ऐसा सिद्धांत तो नहीं कि हमारा जो वर्तमान सिस्टम है इसमें सभी बुराइयों की जड़ को सुधारने का रास्ता खत्म हो गया है और संतुलित आस्था को सामने रखकर यह सभी को आकर्षण कर रहा है? पांचवी चीज, क्या आप अनुभव करते हैं कि कोई बातचीत या डॉयलोग का रास्ता भी है? छटी चीज, क्या आम लोगों की तरफ से सरकारी एजेंसियों को खुद-ब-खुद नक्सलाइट को लोगों का दुश्मन मानकर कुछ सूचना आ रही है? अगर लोगों से सूचना नहीं आ रही है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने नक्सलाइट को अपने मुक्ति दाता, साल्वेशन, दिलवाने वाले नेता तो नहीं मानना शुरू कर दिया?

सर, एक और चीज है,annihilation of class enemies जो थ्योरी है उसमें शोषण होता है including these classes with huge unemployment, and exploitation, particularly small producersजो ट्राइब्स की प्रोड्यूज होती है उसका मुद्दा लोगों को बहुत तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है। मैं एक बात और तजुर्बे के तौर पर कहता हूं कि सिद्धांत में एक मैथ क्रिएट कर दी जाती है, आप जितना उसके नजदीक होकर तोड़ने की कोशिश करोगे उसमें शायद ही सफलता मिले। सन् 1989 में राजीव गांधी जी जिंदा थे और प्रधान मंत्री थे तब मैंने यह मूवमेंट चलाया था कि विदेशों से जितने सिख भारत आ सकते हैं, आने दो। दस सालों में मैं लगभग दो हजार लोगों को यहां लाया और दो हजार यहां से वापस गए। मैं कोई दिशा नहीं बदल रहा हूं। अब दो महीने पहले खालिस्तानियों ने मेरे खिलाफ मीटिंग की और यह कहा है कि जो आदमी विदेश से भारत चला जाता है, पंजाब में दो महीने रहता है, क्या होता है कि यहां अमरीका और कनाडा से आते ही ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? सर, वह खुद देखता है कि पंजाब में न खालिस्तान है, न हिन्दू बनने से झगड़ा है और न ही कोई लड़ाई है, भारत समृद्ध है। तो क्या कोई ऐसी भी योजना हो सकती है, जो लोग उनके नजदीक हैं और किसी न किसी तरह समाज का हिस्सा हैं , हमें उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। इस बारे में श्री वेंकैया जी ने कहा है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): सदर मोहतरम, नक्सलवाद और

उसके जरिए होने वाली बर्बादी पर तफसील से चर्चा हो गई है। मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दो बातों की तरफ दिलवाऊंगा और एक बात मुझे पूछनी है। यह नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ और इसकी बैकग्राउन्ड क्या है? मेरी जहां तक जानकारी है, नक्सलवाड़ी कोई जगह बंगाल में है और वहां से कुछ लोग निकले। अब बंगाल में नक्सलवादियों की सरगर्मियां देखने को नहीं मिल रही हैं मगर यह नक्सलवाद पूरे मुल्क में फैल गया है । लोगों ने वजुहात बहुत सारे बताए हैं कि जमीन का सुधार हो जाए तो यह खत्म हो जाएगा। मै अर्ज़ यह करना चाहता हूं कि ये फोड़े तो जिस्म पर मुसलसल निकलते हैं और इन फोड़ों का इलाज जिन डाक्टरों के जिम्मे है वे टेबलेट्स दे देकर इन फोड़ों को सुखा देते हैं। नतीजा यह होता है, एक जगह सूखता है, दूसरी जगह फूट पड़ता है। अब जरूरत है खराब ब्लड का इलाज करने की , जिसकी वजह से इस तरह के फोड़े निकलते हैं। नक्सलवादी फोड़ा हो, चाहे आतंकवादी फोड़ा हो, चाहे कम्युनिलिज्म का फोड़ा हो, चाहे इलाकों में जात-पांत के भेदभाव के फोड़े हों, इन सारे फोड़ों का रिश्ता एक जैसा है। गरीबी उसका मूल कारण है। लोगों को कानून मौजूद होने के बावजूद भी इन्साफ नहीं मिलता है, संरक्षण नहीं मिलता है। पुलिस मौजूद होते हुए भी लोगों के साथ नाइन्साफी होती है। जुल्म कानून के सहारे किया जाता है, और यह सब कानून की हिफाजत और रक्षा करने वाले करते हैं। ज़ब इस तरह का काम होता है तो लोग निराश होकर गलत हाथों में पड़कर इस्तेमाल होने लगते हैं और मुल्क और कौम को तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं, बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं।

मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोग नक्लवादी हो गए, पहले तो मैं इस काम की मुजम्मत और निन्दा करता हूं कि जो भी काम कानून के दायरे से बाहर निकलकर किया जाए उस काम की हौसला अफजाई कहीं नहीं होनी चाहिए, उसकी मुजम्मत होनी चाहिए। मगर उसकी मुजम्मत करने वालों का जो गिरोह है, वह पार्लियामेंट या असेम्बली में बैठता है। वह मिनिस्टर और एमपी कहलाता है। उस पर नियंत्रण करने के लिए जो थानों में कर्मचारी बैठते हैं वे पुलिस कर्मचारी कहलाते हैं। इनके कैरेक्टर पर भी एक नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से इलैक्शन और सलेक्शन होता है उसमें जिस तरह से गुंडों का इस्तेमाल होता है , जिस तरह से शराब का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से नाइन्साफी और धांधलियों के जरिए जीतने वाला हरवा दिया जाता है और हारने वाला जितवा दिया जाता है। ये सारी की सारी चीजें इस तरह के नक्सलवादियों और अपराधियों को हौंसला बख्शती हैं । जब वे यह देखते हैं कि कानून की हुक्मरानी जिन लोगों के हाथों में है वे लोग ही गलत काम करते हैं छूटते रहते हैं । वे लोग देशद्रोह का काम करते हैं और उनके खिलाफ कानून कोई ऐक्शन नहीं लेता है, वे लोग जो इस

देश में जात-पात, दीन-धर्म के नाम से भेदभाव पैदा करते हैं और इसके बावजूद इज्जत की कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, और ऐसे ही लोगों का मान-सम्मान होता है । जब ऐसी चीजें लोग देखते हैं और अपने साथ नाइंसाफी महसूस करते हैं तब ऐसे लोग उन गलत हाथों में चले जाते हैं । जो लोग कानून की कुर्सियों पर बैठे हैं, इज्जत की कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी जिंदगी से करप्शन खत्म नहीं हो रहा है, उनके माहौल में बुराइयां और बहाइयां खुद जन्म लेती हैं, ऐब को हुनर बना लिया गया है और हुनर को ऐब बना लिया गया है, ऐसी सूरत में वे गरीब लोग भी उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जो लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि बंदूक की गोली से सत्ता को हथियाया जा सकता है । उनको यह यकीन किसने दिलवा दिया कि बंदूक की गोल से सत्ता को हथियाया जा सकता है ? उन लोगों ने उन्हें यह यकीन दिलवाया जिन लोगों ने मुल्क में, सियासत में, सत्ता की रोटी सेकने के लिए अपने अपराधों के जरिए हिंदुस्तान के वातावरण को खराब किया और सत्ता की कुर्सियों तक पहुंच गए । इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसी फिक्र पर पाबंदी लगनी चाहिए जो चीजें नक्सलवाद जैसी बुराइयों को जन्म देती हैं, चाहे वे जिस रास्ते से भी आती हों । मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने नक्सलवादियों से बात करने का प्रोग्राम बनाया है कि खुदा के लिए ऐसा काम न करें और मुख्यधारा में जुड़ जाओ । जिस तरह से हमारी सरकार ने पंजाब में लोगों से बात करने का प्रोग्राम बनाया था, असम में लोगों से बात करने का प्रोग्राम बनाया था । क्या आप ऐसा कोई प्रोग्राम इनके साथ भी बनाने जा रहे हैं कि इन लोगों को गलत रविश से छुड़वाकर सीधी राह पर ले जाकर मुख्यधारा में लगाया जाए ताकि देश का विकास हो सके ।

पुलिस के बारे में भी सभापति महोदय एक बात कहूंगा कि पुलिस का जुल्म भी मामूली नहीं है । लोग लाख पुलिस के मोरल को हाई करने की बात कहें । पुलिस के जुल्म के जरिए भी आतंकवाद फैलता है, मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है, मैंने असल में इन चीजों को देखा है । इस तरह जहां-जहां से चोर रास्तों से आतंकवाद फैलता है और नक्सलवाद फैलता है, उस पर काबू रखने के लिए क्या गृह मंत्री जी कोई उपाय करेंगे ?

श्री नरेश यादव (बिहार) : धन्यवाद सभापति महोदय, नक्सलवाद के बारे में जो चर्चा उठाई गई है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है तथा उसके बारे में सदन की जो राय आई है उससे ऐसा लगता है कि सही मायनों में सदन इस मामले में बहुत गंभीर है और इसका उत्तर हम माननीय गृह मंत्री से गंभीरता से जानना चाहेंगे ।

सभापति महोदय, सिर्फ एक बात कहकर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि अभी यह चर्चा चल रही है कि नक्सलवाद इस देश की एक राष्ट्रीय समस्या है, परंतु यह समस्या कहां से आती है यह मैं श्रीमान् जी के ध्यान में लाना चाहूंगा । इस वाद को आज

आपके प्रयास से लोग नोन पोलिटिकल कहकर समस्या के समाधान के लिए कह रहे हैं । यहां एक मेम्बर जिनका मैं बड़ा मान-सम्मान करता हूं, कमला दीदी जी, वे कहती हैं कि बिहार में जंगल राज है। जनता के द्वारा चुने हुए बहुमत दल के नेता सर्वसम्मति से चुने गए नेता के होते हुए लोकतंत्र के चलते बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद पनपा है और इसकी जड़ में सामाजिक शोषण इसका मुख्य कारण है । यह एक आतंकवादी व्यवस्था है, पर यह कहां-कहां है । श्री आज़मी जी ने बहुत अच्छा कहा कि यह बंगाल से चला था परंतु बंगाल में समाप्त हो गया । लेकिन सभापति महोदय, जहां-जहां सामंतवादी थे, जहां हजारों सालों से एक खास वर्ग को सताया गया था, दबाया गया था, उनके धन पर कब्जा किया गया था , उनके पेट और दिमाग को लूटा गया था, वहां आज इन वर्गों के पास बंदूकें हैं,हाथियारों के लाइसेंस हैं। उनको भय दिखाकर शासन पर उसने कब्जा किया ।

उन वर्गों के पास हथियारों का लाइसेंस है, उनका भय दिखा कर के शासन पर कब्जा उसने किया । जरूर उस समय जो उसने देखा कि यह बंदूक शासन पर कब्जा लाती है, भय दिखा कर के वोट को लूटता है, बंदूक का सहारा उसने लिया जो बहुत गलत है । हम लोग इस बात को गलत मानते हैं । बंदूक के सहारे से कभी भी, किसी भी देश का राज्य की तकदीर नहीं बन सकती है । तकदीर तो बनती है राज्य और देश की, वहां के लोकमत से, वहां की लोकशाही से वरन् तानाशाही से नहीं बनती है । इस बात को हम लोग मानने वाले हैं । इसलिए गृह मंत्री जी इस मामले को सच मानिये, हम चाहते हैं कि इस देश से नक्सलवाद खत्म हो । इसके लिए सामाजिक सुधार आपको नीचे के स्तर से करने की जरूरत है । अगर आप नीचे के स्तर से नहीं, ऊपरी तौर पर चले आए तो कहीं भी सुधार होने वाला नहीं है । जैसे यह कहा गया कि पुलिस का मनोबल बहुत नीचा है । पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और इसी मनोबल के ऊंचा होने के कारण आज अपराध रुके हुए हैं। जब देश में व्यवस्थाएं गिरती हैं, देश की व्यवस्था में भटकाव आता है तो उसका असर पूरे देश की जनता के साथ आता है । आखिर जनता ही पुलिस है, जनता ही एम०एल०ए० है, जनता ही ब्यूरोक्रेट है, सारे लोग वही हैं । इसलिए सच मानिये हम को नीचे से सुधार शुरू करना पड़ेगा । माननीय गृह मंत्री जी ने अंत में कहा है कि सारी समस्याओं के निदान के लिए नक्सलवाद से लड़ने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है । बिहार सरकार नक्सलवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ लड़ रही है लेकिन वहां से अर्द्ध सैनिक बलों को वापिस किया जा रहा है । जो भी मांगा जा रहा है, वह नहीं दिया जा रहा है । जो है, उसको वापिस मांगा जा रहा है । आज बिहार के पास क्या है ? जैसे कि सभी साथियों ने कहा नक्सलवादियों और

उग्रवादियों के खिलाफ आधुनिक हथियार, बारुदी सुरंग बिछाने की क्षमता है लेकिन उनका मुकाबला कैसे किया जाए ? हमारी पुलिस के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि अत्यंत आधुनिक हथियार उनको मुहैया कराए जाएं । नक्सलवादियों और उग्रवादियों के पास आखिर यह आधुनिक हथियार आते कहां से हैं ? उनके पास ए०के०४७, एस.एल.आर. और अत्यंत आधुनिक हथियार उपलब्ध हैं । यह हथियार विदेशों से आ रहे हैं, विदेशों का फाटक खोला जा रहा है । कभी आई०एस०आई० से आ रहा है, कभी उग्रवादी हथियार ला रहे हैं । कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी । जो हथियार आने का रास्ता है, उसको रोकना पड़ेगा । एक बात मैं कहना चाहूंगा । सब से बड़ी जड़ है बेरोजगारी । बेरोजगार युवक क्या नहीं करता । आज बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है । हमें हर गांव में रोज़गार पहुंचाना पड़ेगा, उनको रोज़गार देना पड़ेगा । बेरोजगारों को भटका दिया जाता है । उनसे यह कहा जाता है कि इस सामाजिक व्यवस्था में शोषण है । बेरोजगारों को कहा जाता है देखो वह शोषण है, वह महल है, वह जमीन है, वह बंदूक है । यहां पर दिखाया जाता है कि उनके लिए तबाही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं हैं । उनको यह लगता है कि यह बात सही कही जा रही है । इसलिए हम लोगों को राजनीतिक प्रयास भी करना पड़ेगा, सामाजिक प्रयास भी सर्वांगीण तौर से करना पड़ेगा अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि उग्रवाद समाप्त हो । आज तो आप पांच राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि खास जिलों में नहीं, खास राज्यों में नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में यह फैल रहा है । यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिए इस देश की जनता को और सरकार को मिल कर चलना होगा तभी इसका निदान होगा । हम इस बात का सख्त विरोध करते हैं कि इस तरह से राजनीतिक रूप से इस अच्छी बहस का उपयोग किया जाए। यह अच्छी बात नहीं है । इसलिए मैं गुज़ारिश करना चाहूंगा कि अगर इस देश से नक्सलवाद को हटाना चाहते हैं तो गरीब आदमी जो वंचित है, डिप्रेस्ड है, नीचे की क्लास का है, उनके जीवन में सुधार लाने की जरूरत है । इसको तभी कहा गया था अंत्योदय । वहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा । इसमें उसी क्लास के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं या गरीब आदमी हैं । समाज के वही लोग उसमें लगे हुए हैं, इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुआ है, यह बिलकुल सत्य बात है, इसमें कोई झुठलाने की बात नहीं है । व्यवस्थाएं जातिवादी हैं, जाति के नाम से मान-सम्मान मिला है ।जाति के नाम से अपमान मिला है। जाति के पास में धन रहा है। जाति के नाम से धन से वंचित किया गया है।

जाति के नाम पर धरती छुई जाती थी। यह व्यवस्था इस समाज में रही है। इसलिए बड़े स्तर से, व्यापक तौर से हम लोगों को इस पर प्रयास करना पड़ेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा एक आब्जेक्शन है। उन्होंने कहा है कि ये गरीब लोग और सब लोग नक्सलवाद में लगे हैं। यह सही नहीं है। इसको निकाल दिया जाए। यह तो बड़े लोगों ने शुरू किया है। मैं इसके खिलाफ हूं। यह गरीबों का अपमान है।

श्री नरेश यादव : मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें गरीब लोग, वंचित लोग, डिप्रेस्ड लोग हैं जिनको हजारों सालों से सताया गया है। उनका इस्तेमाल किया गया है। आज इसमें उसी क्लास के लोग हैं। अमीरों के द्वारा गरीबों को सताया गया है। इसलिए अगर हम सचमुच प्रयास करना चाहते हैं तो नीचे से हमें कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा।

आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीगांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय।

महोदय, इस वक्तव्य की पहली लाइन को मैं उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें गृह मंत्री जी ने कहा है - " देश के आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में वामपंथी उग्रवाद चिन्ता का प्रमुख कारण है।" लेकिन मेरी राय में वामपंथी उग्रवाद पैदा होने के कारण का पता

[उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) पीठासीन हुए]

लगाना कहीं इससे अधिक प्रमुख है क्योंकि मेरी राय में जब तक किसी समस्या के कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है तब तक उसका निवारण करना बहुत ही कठिन काम है। अगर कारण का पता लग जाए तो किसी भी समस्या का निवारण करना आसान हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि वामपंथी उग्रवाद पैदा होने का क्या कारण है? क्या इस देश में बेरोजगार नौजवान एवं भुखमरी के शिकार नौजवान उग्रवाद का रूप नहीं ले रहे हैं? जैसे कि कहा जाता है "मरता क्या न करता"। क्या अनावश्यक रूप से पुलिस आतंक के शिकार नौजवान लोग उग्रवाद का रूप नहीं ले रहे हैं? क्या वर्णवाद, जातिवाद एवं सामाजिक विषमता के शिकार नौजवान लोग उग्रवाद का रूप नहीं ले रहे हैं? क्या सामंतवादी आतंकवाद के शिकार नौजवान उग्रवाद का रूप नहीं ले रहे हैं? क्या बैलेट के अधिकार को बुलेट द्वारा रोकने के कारण उग्रवाद नहीं पैदा हो रहा है? क्या हमारे देश में सी०आई०डी०, सी०बी०आई० आदि संगठन उग्रवादियों का पता लगाने में या उसका समाधान करने में विफल नहीं हैं? महोदय, अगर इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखा जाए तो उग्रवाद के ये सब कारण हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर इन सारे प्रश्नों का निवारण

किया जाए तो उग्रवाद को काफी हद तक समापन की ओर ले जाया जा सकता है। धन्यवाद महोदय।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh) : Sir, the menace is very distressing. My friend, Shri Venkaiah Naidu, has explained about the charged atmosphere which is prevailing in our State. The people are panic-stricken. Even the people's representatives are unable to discuss this issue on the floor of the House. Because of their guerilla activities, there are hit-and-run type of cases. We are not aware as to when a person would bekilled. There is total indiscriminate killings. They just want to creat a sensation. Sir, if you make an analysis, originally, we were under the that impression it had got some ideological base.If you critically analyse the contemporary movement, you will find that it is a bunch of lumpen sections who want to amass wealth, who want to indulge in every sort of illegal activity, disturb law and order and create panic conditions. Therefore, virtually, there is no ideological character.

Sir, this menace has to be taken up very seriously. Now it is prevailing in five or six States. Its tentacles are being spread to other States also. If a fire occurs in my house, is it not my duty to put it off? If I put it off prudently, it is okay. Otherwise, it will engulf my neighbour's house also. Therefore, unless the Union Government takes it up very seriously, this menace will engulf the entire country.

We have a very able administrator as our Home Minister. An umpteen number of times I have heard him saying that we should put down terrorism and extremism with an iron hand. However, I am sorry to say that still some more efforts are needed.

Sir, I am not exactly aware of the root cause of this problem in other States. Some Members have given their different versions. However, we have received this legacy. In spite of our best efforts, this problem is very prevalent in parts of Telengana and Rayalaseema areas. Sir, I do admit that these are the areas, which have not been properly developed. In spite of our best policies and reforms, we are unable to attract the investment that is required to set up industries there because of the only reason that these areas are infected with Naxalism.

Sir, I need not explain the intensity of the problem because most of the Members have explained it. This problem has to be taken up very

2.00 P.M.

seriously. We will be discussing a number of issues. However, this is a particular issue where, even if a people's representative in our State speaks about Naxalites, he will not be spared. He cannot see the light of the next day. That is the situation. In spite of the State Government's best efforts in the face of the constraints it is facing, still the problem has to be solved. That is why the State needs the Central Government's help and co-operation.

Sir, one of my friends has said that there should be a strong public opinion. They should be alienated from the rural people. How should we do it? Its causes have to be analysed. Still, some people are sympathetic towards these so-called Naxalites. I do not call them, "Naxalites." They are so-called Naxalites. They try to help some people from more impoverished and deprived sections. They will try to earn the goodwill of those people, and they will create dens in those areas. Whenever the police strikes, they will run away to forests.

Sir, the Karnataka Government and the Tamil Nadu Government are trying to catch hold of a forest smuggler named Veerappan for the past 20 years but have failed in their attempt. The fellow is still at large. If this is the situation, you can imagine the plight of the people who are being terrorised by these Naxalites.

Sir, I want to give some advice. Virtually there is a parallel administration in some districts. This menace is trying to destroy the democratic institutions in the country.

They have created Praja Panchayats. If anybody goes to the court of law to seek justice, he will be killed. They have to go to the court of these Praja Panchayats which are being organised by the Naxalites. There are umpteen number of cases where people, who have gone to the court of law, have either been killed or their limbs have been removed. What I am trying to emphasise is that these State institutions are being demolished by them. The institutions, which we have created and strengthened, are being destroyed.

I would request the hon. Home Minister to strengthen the police force with all modern weapons and treat this menace as a national menace. It is not that they have any ideological base. Had it been so, the solution would

have been different. People say that because of under-development of certain areas in Andhra Pradesh, this movement is thriving there. If it is true, the Government should sympathetically consider developing those areas so that this menace can be confronted on the social front also.

Sir, the hon. Home Minister is a very competant man to put down extremism, but, I think, he has not given much attention to this aspect of the problem. I would request him to kindly now pay attention to this very serious problem and initiate some urgent measures to solve this problem.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, मैं बहुत आभारी हूं इस सदन का और विशेषकर जिन्होंने इस चर्चा का आरम्भ किया श्री संजय निरूपम का, कि उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण सवाल को यहां चर्चा का विषय बनाया एक काल अटेंसन मोसन के माध्यम से।

[श्री सभापति पीठासीन हुए]

सभापति जी, यह सही है कि काल अटेंसन की जो प्रक्रिया यहां पर है और काल अटेंसन की जो प्रक्रिया दूसरे सदन की है, उसमें काफी अंतर है। यहां पर अल्पकाल की बहस सी हो जाती है, यहां केवल स्पष्टीकरण नहीं लिए जाते है, जैसे दूसरे सदन में लिए जाते है, लेकिन, मैंने एक बात पाई कि मार्क्सवादी पार्टी, सीपीएम कीओर से जबहमारे राधाकृष्ण मूर्ति बोले थे और उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से वेंकैया जी बोले थे, तो दोनों वैचारिक दृष्टि से राजनीति के दो छोर हैं, लेकिन सार लगभग समान था। उसी लहजे में बाकी भी अनेक सदस्य बोले, जिनका इस बात पर तो बल था कि नक्सलवादी आंदोलन की उत्पत्ति मूलतया बेरोजगारी, गरीबी, विकास के अभाव भूमि सुधारों का अभाव, न इन समस्याओं में से हुआ है, लेकिन इस बात का भी अहसास था कि धीरे-धीरे करके नक्सलवादी आंदोलन बिगड़ते बिगड़ते, जिसको कहें, कई जगह यह अपराधियों के गिरोह का रूप धारण कर गया और अब एक दूसरे को मरते रहते हैं।

सर, मूलतया नक्सलवाद का जब जन्म हुआ था, मुझे याद है कि कालेज में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टुडेंट थे, बढ़िया से बढ़िया, वह सब नक्सलवाद की ओर आकृष्ट हुए और उसका आधार यह था कि मार्क्सवादी पार्टियों के जो मूल सिद्धांत थे उनको छोड़कर उन्होंने लोकतंत्र का रास्ता अपना लिया है, अब वे चुनाव लड़ने लगे हैं और चुनाव के माध्यम से सोचते हैं कि धीरे-धीरे करके हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आकर हम समाज को

परिवर्तित कर देंगे, यह मार्क्सवाद की कभी कल्पना नहीं थी । मार्क्सवाद की जो मूल कल्पना है, उस मूल कल्पना के हम ही रक्षक हैं, हम ही उसके प्रवर्तक हैं, ऐसा वे सोचने लगे । मैं मानता हूं कि नक्सलवाड़ी में नक्सलवाद ने जन्म लिया और पश्चिमी बंगाल में वह कुछ काल तक रहा, कुछ काल के बाद नहीं रहा तो उसका श्रेय मैं वहां की सरकार को इतना नहीं देता हूं जितना कि मैं सी०पी०एम० और सी०पी०आई० को देता हूं जिन्होंने कि लोकतंत्र को अपनाने के बाद लोकतंत्र को धीरे-धीरे करके स्वीकार कर लिया । शुरू में उनकी भले ही लोकतंत्र में निष्ठा नहीं होगी, शुरू में वे भले ही सोचते होंगे कि we use these platforms to propagate our view-point.

लेकिन शनैः-शनैः उन्होंने लोकतंत्र को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे बाकी सभी लोकतंत्री पार्टियों ने स्वीकार किया और इस कारण यह अनायास नहीं है । दुनियाभर में...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : Just one second. May I point out about it?

SHRI L.K. ADVANI : Yes.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : He will yield. Comrade Lenin had stated in his classical work that in a country where there is a popular voting system and wherein people can change the Government through elections, there is no question of people taking up arms.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : This is what he has mentioned.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : It is a classical system.

SHRI L.K. ADVANI : He is enlightening me about the fact that what is being done now is part of the original Marxism. I can cite so many other quotations which could be quite contrary to this particular quotation. I am not going to debate with you on the issue of Marxism. I don't want to do it. मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैं जब कम्प्लिमेंट पे कर रहा हूं तो भी उनको लैनिन का सहारा चाहिए ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Left- handed compliment.

SHRI L.K. ADVANI : It is not a left-handed compliment. It is very sincere compliment because there are people in the Congress Party who would say, "It was our Government which was able to suppress Naxalism effectively." I am not naming anyone. But I have always held, I have always pointed out to my friends in the Akali Dal Party in Punjab when terrorism

and militancy was at its peak, that they should emulate the two Communist parties of West Bengal when they are dealing with the problem of militancy and how they stood against it. They did not compromise and they did not try to use those element, though they were originally your people and, perhaps, among the best, the youth, particularly, who were attracted to Marxism in those days were among the best really. Anyway, this is typical Gurudas Das Guptaji. Do you want to say that it was original? The world over -- it is not merely the Communist Party of India -- you see what has happened. The world over, there are people who would say that this is the end of history. I have read that famous book by Hukuyama saying that democracy has arrived throughout the world; and this is the end of history. It is a longish debate

इस समय मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाद नहीं है । ऐसा नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में गरीबी नहीं है, केरल में गरीबी नहीं है, वहां बेरोज़गारी भी है, गरीबी भी है और भी बहुत सारी समस्याएं पश्चिमी बंगाल में हैं लेकिन वहां नक्सलवाद नहीं है । अगर चार-पांच प्रान्तों में नक्सलवाद का प्रभाव है तो हम सबको समझना होगा कि वहां सरकार मज़बूती से काम नहीं ले पा रही है । क्योंकि इसका मूल जन्म अभाव में हुआ है, अज्ञान में हुआ है, तो उसके आधार पर अगर कहीं कोई सरकार मजबूती से काम लेती है तो यह कहा जाने लगता है कि ह्यूमन राइट्स सप्रेस हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और यह एक पोलिटिकल ईश्यू है, यह एक सोशियल ईश्यू है, यह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है ऐसा कहा जाता है और अत्यधिक बल उस पर दिया जाता है कि ह्यूमन राइट्स सप्रेस हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रकार के मूवमेंट को रिस्पेक्टिब्लिटी मत दीजिए ।

इस प्रकार की मूवमेंट मूलतः लोकतंत्र विरोधी हैं, लॉ एंड आर्डर का मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं । लॉ एंड आर्डर का तो कोई भी अपराध करेगा, कोई भी हिंसा का रास्ता लेगा चाहिए वह अच्छे काम के लिए भी हिंसा का सहारा लेता है तो भी उसको दंडित करना चाहिए,उसको पकड़ना चाहि, उसको सप्रेस करना चाहिए। लेकिन हम जो राजनीतिक लोग हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हिन्दुस्तान में 1947 में गरीबी के बावजूद, इललिट्रेसी के बावजूद, विकास के अभाव के बावजूद यह निश्चय किया और संविधान ने अपने को उस पर प्रतिबद्ध किया कि हम हिन्दुस्तान में परिवर्तन लाएंगे तो वह लोकतंत्रीय मार्ग से लाएंगे, शांति से लाएंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, संविधान के प्रति हम जब भी राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पर भी आते हैं, तो हम उसकी शपथ लेते हैं। तो सवाल यह है हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान के पौलिटिकल ग्रुप, हिन्दुस्तान के

सोशो-इकोनोमिक ग्रुप, उनकी प्रतिबद्धता है कि हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें। 50 साल से ऊपर हो गया , दुनिया भर में भले ही लोग हमारी आलोचना करें कि इन्होंने इल्लिटरेसी नहीं मिटाई, इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, लोगो को इन्होंने रोजगार नहीं दिया, आज तक कितने ही गांव हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, आज तक भी करोड़ों लोग हैं जिनको सिर छिपाने के लिए छत नहीं है लेकिन इस बात की दुनियां तारीफ करती है कि बावजूद इसके कि इन्होंने लोकतंत्र के प्रति जो अपनी निष्ठा उसे बनाए रखा है। यहां लगातार परिवर्तन होते हैं, अलग-अलग पार्टियां सत्ता में आती हैं और वह आ करके सत्ता संभाल लेती हैं, सब उनके प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। अभी-अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ उस में भारत और पाकिस्तान में कितना कंट्रास्ट है वह एक ही दिन में प्रगट हुआ। एक दिन वहां जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा करके वहां पर सैनिक शासन आता है और उसके अगले दिन यहां पर लोकतंत्रीय ढंग से चुनी हुई नई सरकार अपना स्थान लेती है। इस कारण मैं मानता हूं कि नक्सलवादी के सवाल के साथ-साथ हमें बाकी सारे पहलूओं को भी देखना है। हमें विकास की तरफ ध्यान देना है। जो सहायता राज्य को चाहिए हमको वह राज्य को देनी है। सुरेश पचौरी जी ने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे साधन सीमित हैं। यह थोड़ी है कि कोई कहेगा कि हमको पांच सौ करोड़ चाहिए और मिल जाएगा। कुल मिलाकर, डवलपमेंट स्कीम भी उसमें डालकर के, मध्य प्रदेश ने 500 करोड़ मांगा है। तो हमने कहा कि ये सारी जो डवलपमेंट की स्कीम है उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, यह आपप्लानिंग कमीशन से डिस्कस करिये और इस कारण उनका जो एक्शन प्लान, वह चाहे आंध्र हो चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उड़ीसा की, - संजय निरूपम जी को जानकारी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र ने नहीं भेजी है, महाराष्ट्र ने एक्शन प्लान नहीं भेजा है, जिसका निर्णय हमने हैदराबाद में किया था। जो हमारे पास आएगा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर जो डायरेक्टली है या पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए, हमने जो अपने वायदे किये हैं उनकी पूर्ति करने में हम देर नहीं करते। लेकिन उसके अलावा और जो बातें, प्लानिंग कमीशन ही उसका निर्णय करेगा और उसमें हमारी तरफ से कोई कसर नहीं होगी।

मैं समझता हूं कि कई बातें और हैं। जिनको मैं स्पेसिफिकली लेता हूं। अब आंध्र प्रदेश और बिहार प्रदेश हैं। इनमें उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि कोई उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहे या नक्सलिज्म कहे, यह दोनों शब्द धीरे-धीरे करके पर्यायवाची हो गये हैं। आखिर तो नक्सलिज्म कहने से भी तो कोई कह सकता है कि नक्सलवाड़ी में कहेगा कि किस के लिए मेरे नाम से यह काम जोड़ दिया है। नक्सलवादी वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है और चूंकि वहां पर इस प्रकार का दृष्टिकोण

या इस प्रकार का विचार आरम्भ हुआ। यह मार्क्सवादी जो भी बातें कहते हों और सोचते हों कि लोकतंत्र के मार्ग से हम निकाल लेंगे, लेकिन यह नहीं निकाल पाएंगे। ये जो असली मार्क्सवादी अपने को कहते हैं और ऐसी जो भी अपनी संख्याएं बनाते हैं, कितने ऐसे संगठन हैं जिनको नक्सलवादी कहा जा सकता है या लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जा सकता है। मुझे जो सूची भेजी गई है वह लगभग 35 संगठनों की है और 35 संगठनों में मैं देखता हूं कि अधिकांश में कम्युनिस्ट शब्द आता है। लेकिन कम्यूनिस्ट हैं, कहीं पर मार्क्ससिस्ट हैं, कम्यूनिस्ट रिवोल्यूशनरीज है, कहीं-कहीं पर नहीं आता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मार्कसिस्ट रेब्युल्यूशनरीज युनीटी सैन्टर है, युनिटी कमेटी आफ कम्युनिस्ट रेब्युल्यूशनरीज है और यही कारण है कि ये दोनों शब्द, नक्सलवादी और वामपंथी उग्रवाद एक से हो गए हैं। इसका अर्थ कोई सी. पी. आई. और सी. पी. एम. पर कमेंट करने का नहीं है। सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के बारे में मुझे जो अपना मत व्यक्त करना था, वह मैं पहले ही कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि रेस्पेक्टोबिलिटी नहीं देनी चाहिए, डेवलपमेंट के काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहां तक एक्चुअली नक्सलवादी अपराध के डील करने का सवाल है, अगर पूरे समय सदन में यह आभास मिलेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उससे काम इसलिए नहीं चलेगा कि सरकार इस बारे में करे कि प्राईमरी रेस्पॉन्सबिलिटी सैन्टर गवर्नमेंट की नहीं है। In so far as police is concrned, in so far as public order is concerned, under the Constitution, is with the State . लेकिन यह बात सही है कि पिछले पन्द्रह बीस सालों में लॉ एंड आर्डर की प्रोब्ल के साथ जुड़कर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जैसे आई. एस. आई. का उग्रवाद,जैसे नक्सलवादी मूवमेंट, जिसके कारण केवल मात्र किसी छोटे क्षेत्र में या प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए संकट पैदा होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि It is not alocal phenomenon, it is a matter of national concern. और उस स्थिति में केन्द्र सरकार, चाहे वह आई एस आई द्वारा पैदा किया हुआ उग्रवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, हमने उन प्रदेशों से कहा कि जो भी सहायता हम दे सकते हैं देंगे, प्रशिक्षण चाहे तो वह देंगे और सहायता चाहिए तो वह हम देंगे और इस दिशा में हम लगातार चलते रहे हैं। लेकिन मैं पंजाब के अनुभव के आधार पर सदन में कहना चाहता हूं।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I agree with the hon. Home Minister on that proposition. But it is an inter-state problem. It needs coordination and an initiative from the Centre.

SHRI L.K. ADVANI: I entirely agree with that. I do not dispute it.

Thereafter, after the Vajpayee Government came to power--I do not know whether such an effort had been made earlier-- but for the first time, the Chief Ministers of the Naxalite affected States, and all the DGPs of those areas, were brought together at Hyderabad, and subsequently also, as I have spelt out in my own statement, a coordination centre was set up, and during the last less than one year, four meetings have been held, and in those meetings, we took stock of the situation and the progress made, and I can say, even the statistics that I have with me, indicate that in Andhra Pradesh, where in 1996, there were 933 incidents of naxalite violence in which 186 citizens lost their lives, in 1999, it has come down to 427 in which 125 persons have died. Now, I do not proceed only on the basis of those statistics. But as I have said in my statement also, there is an earnest effort in certain States to control this, and some measure of success has been achieved, though there is no full success, and a lot more needs to be done. Coordination is necessary, and as has been rightly said...उनके पास तो सोफेस्टिकेटेड हथियार हैं और हमारा पुलिस कांस्टेबल जो है वह साधारण सी बंदूक लेकर काम करता है। इस दृष्टि से के लिए भी हम जितनी सहायता दे सकते हैं, हम देंगे और हम दे रहे हैं। लेकिन मध्यप्रदेश में जो घटना घटी है, इस प्रकार की घटना कभी -कभी हो जाती है जिसमे किसी एक को चुन कर मारा जाता है। इसके कारण आन्ध्र प्रदेश में अभी-अभी कुछ प्रमुख नक्सलवादी नेताओं को एक एनकाउन्टर में मार दिया गया था। जिनकी संख्या तीन या चार थी। उसके तुरन्त बाद यह दिखाने के लिए कहा कि हम अभी भी हैं उन्होंने मध्यप्रदेश चुन लिया है। मध्यप्रदेश में बालाघाट पर जाकर वहां के एक मंत्री की इस प्रकार नृशंस और निर्मम हत्या की। बहुत ही बुरी तरह से हत्या करके यह लिखा दिया कि यह हम इस कारण कर रहे हैं, हम हैं नक्सलवादी और हम जानबूझकर यह कर रहे हैं। ताकि आपको पता लगे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । लेकिन उसके कारण कुल मिलाकर जिस प्रकार का एफोर्ट हो रहा है उसे कम नहीं आंकना चाहिए । हम उस दिशा में सतत् कदम उठाते रहेंगे और जिस प्रकार की आज यहां चर्चा हुई, उससे लगता है कि सभी को इस बात का अहसास है कि लोकतंत्र के माध्यम से, शांति के रूप में जो भी परिवर्तन हमें करने हैं हम वे करेंगे । उसके आधार पर यदि कोई ऐसा वर्ग है, जो प्रचार करना चाहता है तो शांति और लोकतंत्र के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह पूरा का पूरा सदन उनकी इस विचारधारा के खोखलेपन को दुनिया भर के सामने रखने को तैयार है, उद्धत है । हरेक ने यह बात कही, किसी ने दूसरी बात नहीं कही ।

श्री बलबन्त सिंह रामूवालिया : सर,आप पंजाब के बारे में कुछ बता रहे थे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पंजाब के बारे में याद दिलाया । पंजाब के बारे में मैं कह रहा था कि पंजाब में सेना भेजी गई, पंजाब में पैरा मिलिट्री फोर्स भी बहुत सक्रिय रही, कई वर्षों तक रही, लेकिन अंतोगत्वा वहां पर उग्रवाद को हम पराजित कर सके और उस पर काबू पा सके तो उसका श्रेय वहां की जनता को, सरकार की सेना को और वहां की पुलिस को मैं विशेष रूप से देता हूं । पुलिस अगर सक्रिय होकर इस प्रकार की समस्याओं का मुकाबला न करे तो सेना और पेरा मिलिट्री फोर्स कुछ नहीं कर सकती अर्थात् अगर पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, कांस्टीट्यूशन में जो स्टेट्स का विषय बनाया गया है वह अकारण नहीं बनाया गया है, यह सोच-विचार करके बनाया गया है कि आखिरी तो काम वहीं की पुलिस करेगी, वहीं की सरकार करेगी । केंद्र की सरकार की ओवरआल रिस्पोंसिबिलिटी है को-ऑर्डिनेशन की, ओवरआल रिस्पोंसिबिलिटी है असिस्टेंस देने की, ओवरआल रिस्पोंसिबिलिटी है शिक्षण देने की, ओवरआल रिस्पोंसिबिलिटी है कि स्टेट के जो अपने रिसोर्सज हैं, वे कम हों तो उनके रिसोर्सज को मजबूत करने के लिए केंद्र सहायता दे, ये सब केंद्र की रिस्पोंसिबिलीटीज हैं जिनको पूरा करने के लिए हममें जितना सामर्थ्य है उसे हम कर रहे हैं लेकिन सफलता मूलतः तभी मिलेगी जब वहां की सरकार सक्रिय होगी, वहां की जनता का मन साफ होगा कि उग्रवाद का रास्ता हमें स्वीकार नहीं है । अभी रामूवालिया जी ने कहा कि विदेश से लोग आते हैं और लौटकर जब जाते हैं, कनाडा, अमरीका में तो कहते हैं कि क्या हो गया है । यह जो पहले का देश था, जो पहले का गुस्सा था, वह नहीं रहा । इसका कारण हम स्वयं देखते हैं । मैं स्वयं जानता हूं कि जब 1987-88 में जब मैं पंजाब जाता था तो स्थिति को देखकर बहुत दुख होता था कि चारों ओर सुनसान ही सुनसान है । शाम के पांच-छः बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता । गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता और जो प्रमुख हिस्से हैं पंजाब की जनता के उनके बीच इतना अविश्वास था कि यदि कोई किसी दूसरे से बात करता था तो कहा जाता था कि यह क्या कर रहे हो, हमारे नेता होकर वहां जाकर बात करते हो । इनको तो उनसे बात नहीं करनी चाहिए । इतना गहरा अविश्वास था । उस अविश्वास को बिल्कुल समाप्त करके अब जो परिवर्तन पंजाब में आया है, इस समय, वह परिवर्तन जनता के कारण आया है, प्रदेश की सरकार के कारण आया है और प्रदेश की पुलिस के कारण आया है । इस तथ्य को समझकर ही जिन-जिन प्रदेशों में आज नक्सलवादी समस्या है उस नक्सलवादी समस्या का हम मुकाबला करें और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से उग्रवाद को पंजाब में हमने समाप्त किया उसी प्रकार से बाकी क्षेत्रों में, चाहे उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में हो, चाहे कश्मीर में हो या किसी और इलाके में हो वहां पर भी हम उनके साथ जूझ रहे हैं तथा उसी प्रकार से नक्सलवादी तत्वों पर विजय पाएंगे, सफलता पाएंगे और

उसकी जवाबदेही सबको करनी चाहिए । एक बार मैं पुनः सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मूल समस्या की ओर सही प्रकाश डाला ।

FAREWELL TO THE RETIRING MEMBERS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, two Members of this House from Delhi, namely, Shri K.R. Malkani and Shri O.P. Kohli, are retiring on the 27th January, 2000 on the completion of their term of office. I take this opportunity to bid them farewell. I am sorry, Mr. Malkani is not present here, though we had sent him the message. The retiring Members made valuable contribution to the proceedings of the House. I hope the Members who are leaving us will cherish the memory of their association with this august House. I wish them good health, happiness and success in every sphere of life. The House shall fondly remember their association.

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, इस गरिमापूर्ण सदन में सदस्य के रूप में बिताए छः वर्ष मेरे लिए बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद रहे हैं । इन छः वर्षों में मैंने सदन के माननीय सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है - उनके भाषणों और चर्चाओं की गहराई से भी और उनकी अपनी बात कहने की शैली से भी । संसद सदस्य न रहने पर भी यहां से जो कुछ सीखा है, वह राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में मुझे अपना कार्य करने में बहुत उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा ।

सदन के आदरणीय सभापति जी और पीठासीन उपसभाध्यक्ष महोदयों के प्रति भी मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझ जैसे प्रथम बार के सदस्य के प्रति बहुत ही अनुकूल रुख रखा और सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान करने में उदारता दिखाई ।

सदन में कभी-कभार उत्तेजना और हंगामे की स्थिति पैदा होने पर हो सकता है मेरे व्यवहार से भी कुछ उत्तेजना आई हो । यदि इससे किसी भी सदस्य की भावना को चोट पहुंची हो तो क्षमा चाहूंगा ।

मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से तथा पार्टी के अन्य सदस्यों से जैसा स्नेह और आत्मीयता प्राप्त हुई है, वैसी ही आत्मीयता अन्य दलों के माननीय सदस्यों से भी प्राप्त हुई है । मैं विपक्ष के नेता श्री मनमोहन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा । जब भी कभी उनसे बात करने का मुझे अवसर मिला, मन को छूने वाला स्नेह उनकी बातों में भरा था । इसके लिए मैं उन के प्रति आभार